दैनिक
सामुदायिक प्रेषण
कलम की ताकत और जनता का विश्वास
क्षेत्र का अग्रणी मीडिया समूह से जुड़ने के लिए सम्पर्क करें- 92566 95106
● जयपुर से प्रकाशित ● खबरों में निरन्तरता , निष्पक्षता और निड़रता ●RNI.NO - RJHIN/25/A3277
वर्ष : 1 | अंक : 174 | हिन्दी | दैनिक | शुक्रवार 1 मई 2026 | कुल पृष्ठ - 4 / पीडीएफ - 6 | संपादक - ओमप्रकाश जागिड़

सुविचार

'इंतजार नहीं, एक्शन जरूरी है। जो लोग मौके का इंतजार करते रहते हैं, वे पीछे रह जाते हैं और जो तुरंत कदम उठाते हैं वही आगे निकल जाते हैं '।

सुप्रीम कोर्ट बोला-रेप विक्टिम के अबॉर्शन पर टाइम लिमिट हटाएं

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की रेप विक्टिम को 30 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में अबॉर्शन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने केंद्र से कहा कि ऐसे मामलों में अबॉर्शन के लिए टाइम लिमिट से जुड़े कानून में बदलाव करना चाहिए।। CJI ने कहा, 'कानून ऐसा होना चाहिए, जो समय के साथ बदलता रहे और मौजूदा हालात के अनुसार चले। नाबालिग को जबरन मां बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में फैसला पीड़ित का ही होना चाहिए।' सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को करीब सात महीने प्रेग्नेंट 15 साल की लड़की को अबॉर्शन की इजाजत दी थी। इसके खिलाफ AIIMS ने याचिका लगाई थी। क्योंकि अभी भारत का कानून रेप मामलों में 24 हफ्ते तक की प्रेग्नेंसी में ही अबॉर्शन की इजाजत देता है।

किसी हाल में न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ेंगे:ईरान

अमेरिकी ठिकाने खुद सुरक्षित नहीं, वो दूसरों को क्या बचाएंगे

तेहरान/वॉशिंगटन डीसी।

ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई ने एक बयान जारी कर कहा कि उनका देश अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमता से किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगा। उनका यह लिखित बयान ईरान के सरकारी टीवी पर पढ़कर सुनाया गया। खामेनेई ने कहा कि ईरान अपनी 'परमाणु और मिसाइल ताकत' को देश की संपत्ति मानता है और हर हाल में उसकी रक्षा करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में अब एक नया दौर शुरू हो गया है, जो आगे चलकर इलाके में शांति, तरक्की और आर्थिक फायदा लाएगा। खामेनेई ने कहा कि अमेरिका के सैन्य ठिकाने (बेस) इतने कमजोर हैं कि वे खुद की सुरक्षा भी ठीक से नहीं कर सकते। ऐसे में वे इस इलाके के दूसरे देशों को सुरक्षा देने का दावा कैसे कर सकते हैं

जंग में अमेरिका के 25 अरब खर्च: अमेरिका ईरान युद्ध पर पिछले 2 महीने में अब तक 25 अरब डॉलर खर्च कर चुका है। अमेरिका ने पहली बार जंग में हुए खर्च की जानकारी दी है।

2. ट्रम्प ने राइफल के साथ फोटो शेयर की: ट्रम्प ने राइफल के साथ फोटो पोस्ट कर ईरान को चेतावनी दी। फोटो पर लिखा था- नो मोर मिस्टर नाइस गाइ (मैं नरमी नहीं बरतूंगा)।

3. ईरान ने UN में अमेरिका की शिकायत की: ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में शिकायत कर अमेरिका पर जहाज जब्त करने और 38 लाख बैरल तेल कब्जाने का आरोप लगाया।

4. लेबनान में 12 लाख लोगों पर भुखमरी का खतरा: UN से जुड़ी रिपोर्ट में कहा गया कि युद्ध, विस्थापन और आर्थिक दबाव के कारण लेबनान में 12 लाख से ज्यादा लोग खाद्य संकट झेल सकते हैं।

5. भारत-ईरान विदेश मंत्रियों की फोन पर बातचीत: विदेश मंत्री एस. जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने युद्धविराम, द्विपक्षीय रिश्तों और क्षेत्रीय हालात पर फोन पर चर्चा की।ईरान में लोग मानते हैं कि ऐसा सुरक्षा कारणों से किया जाता है। अमेरिका और इजरायल की तरफ से 'टॉप लीडर को निशाना बनाने' की नीति (डिकैपिटेशन पॉलिसी) का खतरा माना जाता है, इसलिए उनकी सुरक्षा को लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है।

ईरानी सुप्रीम लीडर की सेहत पर सस्पेंस, टीवी पर बयान पढ़ा गया

ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई की सेहत को लेकर अब भी साफ जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम लीडर बनने के बाद से वह कभी भी सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए हैं। उन्होंने अब तक कोई वीडियो या ऑडियो संदेश भी जारी नहीं किया है। उनके सभी बयान हमेशा लिखित रूप में आते हैं, जिन्हें सरकारी टीवी पर पढ़कर सुनाया जाता है। ईरान में लोग मानते हैं कि ऐसा सुरक्षा कारणों से किया जाता है। अमेरिका और इजरायल की तरफ से 'टॉप लीडर को निशाना बनाने' की नीति (डिकैपिटेशन पॉलिसी) का खतरा माना जाता है, इसलिए उनकी सुरक्षा को लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है।

ईरानी राष्ट्रपति बोले- हमारे पोर्ट की नाकाबंदी अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने कहा कि अमेरिका की समुद्री नाकाबंदी कामयाब नहीं होगी। ईरान के बंदरगाहों को रोकने की कोई भी कोशिश आखिर में फेल ही होगी।पजशकियान ने कहा कि इस तरह की नाकाबंदी अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और इससे दुनिया की शांति पर भी असर पड़ता है।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा: कार में आग लगने से 6 लोग जिंदा जले, वैष्णो देवी से लौट रहे थे सभी

सभी मृतक मध्य प्रदेश के श्योपुर के रहने वाले थे और वैष्णो देवी से दर्शन कर लौट रहे थे.

अलवर

जिले के मौजपुर के एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर के पास बुधवार देर रात को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलती कार में आग लग गई. घटना में एक ही परिवार के 6 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई. वहीं, कार चालक भी गंभीर रूप से झुलस गया है, जिसे इलाज के लिए जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. सूचना मिलने पर मौके पर लक्ष्मणगढ़ पुलिस और दमकल पहुंची और आग पर काबू पाने के

प्रयास किए. एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर के जवान भी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में सहयोग किया. घटना की सूचना मिलने के बाद अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी एवं डीएसपी कैलाश जिंदल मौके पर पहुंचे. एक ही परिवार के 5 लोग जले : एसएसबी के इंस्पेक्टर जितेन्द्र कुमार ने बताया कि बुधवार देर रात को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रेनिंग सेंटर के जवान गाड़ी में आग लगती देख मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया. आग के विकराल रूप ले लिया था. कार के चालक विनोद मेहर को जवानों ने रेस्क्यू कर अलवर के जिला अस्पताल पहुंचाया. कार में 2 महिला, 2 बच्ची एवं 2 व्यक्ति जल गए. ये सभी लोग मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के चैनपुरा गांव के रहने वाले थे, जो कि वैष्णो देवी के दर्शन कर कर वापस अपने गांव लौट रहे थे. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, केमिकल के ड्रमों से भरे ट्रक में जा घुसी बस, 3 की मौत, 30 घायल अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि बुधवार देर रात करीब 11 बजे आग लगने की घटना हुई. मध्य प्रदेश के श्योपुरा जिले के चैनपुरा निवासी एक परिवार किराए की टैक्सी लेकर आया था. कार में गैस रिसाव के कारण आग लग गई. कार में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे गाड़ी में सवार कोई भी सदस्य बाहर नहीं निकल सका. हादसे में दो महिलाएं, एक पुरुष और दो बच्चियों की जलने मौत हो गईचालक को जयपुर रेफर कर दिया: वहीं, गाड़ी चालक कार का शीशा तोड़कर बाहर कूद गया, जिसे गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया था, जहां से चालक को जयपुर रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई।

भारत-इटली के रक्षा मंत्रियों की द्विपक्षीय वार्ता, सैन्य सहयोग योजना पर सहमति

नई दिल्ली ।

नई दिल्ली में गुरुवार को भारत और इटली के बीच रक्षा मंत्रियों की द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता का उद्देश्य रक्षा सहयोग को नई मजबूती देना है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, थलसेना प्रमुख जरनल उपेंद्र द्विवेदी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो के साथ यह वार्ता दिल्ली के मानेकशॉ केंद्र में हुई। इस दौरान दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया, जो शांति, स्थिरता, स्वतंत्रता और आपसी सम्मान जैसे साझा मूल्यों पर आधारित है। बैठक में दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। खासतौर पर पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उत्पादन में सहयोग बढ़ाने और इटली के साथ मिलकर रक्षा क्षेत्र में नई संभावनाओं को विकसित करने पर भी सहमति बनी। यह पहल दोनों देशों की सैन्य और औद्योगिक क्षमता को भविष्य में और मजबूत बनाने में मदद करेगी।

ऑपरेशन सिंदूर को अपनी शर्तों व समय पर अंजाम दिया: राजनाथ सिंह

नई दिल्ली।

ऑपरेशन सिंदूर ने वैश्विक स्तर पर स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत आतंकी हमले होने की स्थिति में अब केवल कूटनीतिक बयान जारी करने की पुरानी मानसिकता से बंधा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से अपनी अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने

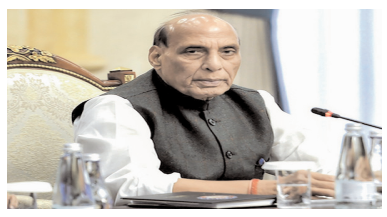

ऑपरेशन सिंदूर को अपनी शर्तों और अपने चुने हुए समय पर अंजाम दिया और इसे पूरी तरह अपनी शर्तों पर ही रोका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कहा, सरकार का दृढ़ रुख है कि किसी भी परिस्थिति में आतंकवाद के किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, हवाई हमले और ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खतरे के खिलाफ सरकार के दृढ़ रुख का प्रमाण बताया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान, हमने पूरी सटीकता के साथ केवल उन्हीं लोगों को निशाना बनाया।

सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच से जुड़ी याचिकाएं खारिज

बेंच बोली- हम संसद को कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हेट स्पीच से जुड़ी याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि अदालत संसद को कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि

इस मुद्दे पर कानून बनाना विधायिका का अधिकार है। अदालत केवल जरूरत की ओर ध्यान दिला सकती है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि नीति बनाना और कानून तैयार करना विधायिका के दायरे में आता है। अदालत इसमें दखल नहीं दे सकती। कोर्ट ने यह फैसला उन याचिकाओं पर दिया, जिनमें केंद्र सरकार को हेट स्पीच और अफवाह फैलाने से जुड़े कानूनों की समीक्षा कर नया कानून बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

राजस्थान में आंधी-बारिश से मिली गर्मी से राहत, अगले 4-5 दिन बारिश की संभावना

जयपुर/भरतपुर:

राजस्थान में कुछ जगहों पर आंधी-बारिश के कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है. वर्तमान में अधिकतर जगहों पर तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है. आगामी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से चार-पांच दिन दोपहर बाद तेज आंधी और बारिश होने की संभावना है. प्रदेश में सबसे अधिक तापमान चित्तौड़गढ़ में 43.4 डिग्री सेल्सियस और फलोदी में 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, भरतपुर में बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक प्रदेश में कहीं-कहीं हीट वेव और उष्ण रात्रि दर्ज की गई है. इसके साथ ही कहीं-कहीं मेघगर्जन और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश भी हुई है. पिछले 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक बारिश हनुमानगढ़ में 13 मिलीमीटर दर्ज की गई है।

भाजपा विधायक को अधिकारियों ने पीटा

:जयदीप बिहाणी बोले-मेरे चेहरे पर वार किए, लोगों ने कहा-रुकने अफसरों को गाली दी, मारपीट की

श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर से भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी के साथ जनसुनवाई के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है। विधायक का आरोप है कि श्वह समेत तीन अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट की। विधायक ने कहा- मेरी एक आंख और चेहरे पर चोट आई है, मेरा चश्मा भी टूट गया है। विधायक की शिकायत पर जवाहर नगर थाना पुलिस ने तीनों अधिकारियों RUIDP के AEN जगनलाल बैरवा, प्रोजेक्ट मैनेजर शहनवाज और L&T कंपनी के प्लानिंग मैनेजर सोएम को गिरफ्तार किया है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि राजस्थान अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (RUIDP) के

अफसर जब विधायक केंद्र पहुंचे तो विधायक ने गालियां देनी शुरू कर दी। दो अफसरों के साथ मारपीट की गई, इसमें एक की शर्ट फट गई, जिसे नई शर्ट लाकर दी गई। इस दौरान कर्मचारियों के फोन भी जब्त कर लिए गए। मामला एसडी बिहाणी कॉलेज में संचालित विधायक सेवा केंद्र में गुरुवार सुबह 11 बजे का है। जवाहर नगर थाने के सीआई देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि विधायक के साथ मारपीट करने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।विधायक बोले- RUIDP के अफसर जिम्मेदारी थोप रहे थे

AEN ने मुझ पर हमला किया, चेहरे पर मारा

विधायक बिहाणी ने बताया- मैं उनसे बस इतना पूछ रहा था कि क्या आपको जनता की कोई चिंता है या नहीं? यह कहते ही RUIDP के AEN जगनलाल बैरवा ने मुझ पर हमला बोल दिया। उन्होंने मेरा चश्मा तोड़ दिया और आंख के नीचे चोट पहुंचाई। मैंने पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और तीन अधिकारियों को पकड़कर ले गई। विधायक ने कहा कि तीनों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जा रही है। मैंने इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को शिकायत करने की भी बात कही है।

विधायक ने कहा- RUIDP और L&T कंपनी ने पूरे शहर की पानी सप्लाई को बाधित कर रखा है। पुरानी आबादी और करणपुर रोड क्षेत्र में पिछले 7 दिनों से पानी की एक बूंद नहीं पहुंच रही है। लोगों को बाथरूम जाने तक का पानी नहीं मिल पा रहा है। इनके पास न लाइनमैन है, न वालमैन। समस्या बताने पर ये PHED पर जिम्मेदारी थोप देते हैं, जबकि PHED अधिकारी कहते हैं कि उनके पास पर्याप्त स्टोरेज है और जरूरत पड़ने पर पूरे शहर को सप्लाई कर सकते हैं। इस गंभीर समस्या को लेकर विधायक सेवा केंद्र में मीटिंग बुलाई गई थी। एक्सईएन किशन धारीवाल ने सुबह 9:30 बजे और फिर 11 बजे RUIDP व L&T अधिकारियों को फोन कर बुलाया, लेकिन वे नहीं पहुंचे। जब मैं खुद जाने लगा तो RUIDP के सहायक अभियंता (AEN) जगनलाल बैरवा और प्रोजेक्ट मैनेजर शाहनवाज विधायक सेवा केंद्र पहुंच गए।

जिला कलक्टर ने किया जे.के. लोन बाल चिकित्सालय का औचक निरीक्षण

दवाओं-उपकरणों की निरंतर उपलब्धता, स्वच्छता में सुधार के दिए निर्देश

सामुदायिक प्रेषण

जयपुर। राज्य सरकार बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील है एवं उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध भी है। जिला कलक्टर संदेश नायक द्वारा जयपुर स्थित जे.के. लोन बाल चिकित्सालय का गुरूवार को औचक निरीक्षण किया गया। यह चिकित्सालय जयपुर का एक प्रमुख एवं बड़ा बाल चिकित्सालय है, जहां बड़ी संख्या में बच्चों का उपचार किया जाता है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चिकित्सालय के विभिन्न विभागों एन.आई.सी.यू., आईपीडी, ओपीडी एवं वार्डों का अवलोकन किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रयोगशाला की व्यवस्थाओं क समीक्षा की। उन्होंने उपचाराधीन बच्चों के परिजनों से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को भी सुना। निरीक्षण में जिला कलक्टर ने पाया कि चिकित्सालय में चिकित्सकीय सेवाएं नियमित रूप से प्रदान की जा रही हैं, हालांकि कुछ व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने मरीजों को समय पर एवं गुणवत्तायुक्त उपचार सुनिश्चित करने, साफ-सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था को आर सुदृढ़ करने, आवश्यक दवाइयों-उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं परिजनों को बेहतर सुविधा एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए । कलक्टर द्वारा चिकित्सालय प्रशासन को यह भी निर्देशित किया गया कि बच्चों के उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए तथा सभी व्यवस्थाओं की नियमित मॉनीटरिंग की जाए।

निरीक्षण के दौरान प्राप्त सुझावों के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर शुक्रवार को

सामुदायिक प्रेषण

चूरू, । जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र द्वारा शुक्रवार, 01 मई, 2026 को सवेरे 11 बजे तारानगर पंचायत समिति सभागार में औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर आयोजित किया जाएगा। उद्योग महाप्रबंधक नानुराम गहनोलिया ने बताया कि शिविर में तारानगर के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं, उद्यमियों, बेरोजगारों को उद्योग विभाग की डॉ भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी, राजस्थान ओडीओपी पॉलिसी, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी आदि विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उद्योग/सेवा क्षेत्र व व्यवसाय के क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर विभागीय योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

स्व. युविराज सिंह भाटी की स्मृति में महाविद्यालय में शीतल जल मंदिर का भव्य उद्घाटन

सामुदायिक प्रेषण

रमेश जांगिड उनियारा,टोंक। स्थानीय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गुरुवार को एक गरिमामयी समारोह के बीच 'शीतल जल मंदिर का उद्घाटन संपन्न हुआ। इस जल मंदिर का निर्माण भाटी परिवार द्वारा अपने दिवंगत पुत्र युविराज सिंह भाटी की पुण्य स्मृति में महाविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु करवाया गया है। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ प्रातः 11:00 बजे मुख्य अतिथि महेंद्र सिंह भाटी द्वारा शीतल जल मंदिर की पत्रिका का अनावरण कर किया गया इसके पश्चात महाविद्यालय परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एव दीप प्रज्जवलित किया गया। महाविद्यालय स्टाफ द्वारा मुख्य अतिथि महेंद्र सिंह भाटी उनकी धर्मपत्नी मंजू भाटी एवं उनके परिवार जनों का माला पहनकर आत्मीय स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य पानिमल पहाड़ियां ने मुख्य अतिथि को सापा पहनाकर एवं अभिनंदन पत्र भेंट कर महाविद्यालय की ओर से विशेष सम्मानित किया। कार्यक्रम के समन्वयक धर्मेन्द्र सिंह चाहर ने सभी आगंतुकों और अतिथियो का स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि महेंद्र सिंह भाटी ने अपने आशीर्वचन में विद्यार्थियों के लिए भावी और परोपकार के महत्व पर प्रकाश डाला। प्राचार्य पानिमल पहाड़िया नि भाटी परिवार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस पुनीत कार्य से समाज के अन्य लोग भी जन सेवा के कार्य के लिए प्रेरित होंगे। संपूर्ण कार्यक्रम का कुशल संचालन डॉ. भानू प्रकाश शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय परिवार के सदस्य दिव्या मीणा, आशीष यादव,राजेश यादव, मिनाली रमेश, प्रोफेसर विशाल काटया सहित कार्यालय सहयोगी अभिषेक शर्मा, आशीष जैन, एव मनोज बैरवा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में डॉ. दिविराज झांझरिया ने सभी अतिथियो और उपस्थित जनसमूह का धन्यवाद ज्ञापित किया। समारोह में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं एंव गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

नीट (यूजी) परीक्षा 2026 के सफल आयोजन हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

परीक्षा में सुरक्षा, गोपनीयता एवं निष्पक्षता बनाए रखने पर विशेष जोर

सामुदायिक प्रेषण

जयपुर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित नीट (यूजी) परीक्षा 2026 के सफल, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष आयोजन के लिए जिला प्रशासन जयपुर द्वारा व्यापक तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक द्वारा संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलक्टर ने पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, कानून-व्यवस्था एवं सुचारू यातायात सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार पुलिस बल की तैनाती की जाए तथा अनाधिकृत प्रवेश पर पूर्णतः रोक लगाई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि परीक्षा से संबंधित गोपनीय सामग्री का सुरक्षित संधारण एवं वितरण सुनिश्चित किया जाए। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों पर परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना या सामग्री के प्रसार पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश भी दिए। जिला कलक्टर ने निर्देशित किया कि परीक्षा दिवस पर परीक्षा केंद्रों के 300 मीटर के दायरे में फोटोकॉपी, साइबर कैफे एवं अन्य संबंधित दुकानों को बंद रखा जाए, जिससे किसी प्रकार की अनियमितता की संभावना न रहे। उन्होंने जयपुर नगर निगम को परीक्षा केंद्रों के आसपास साफ-सफाई एवं आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, वहीं विद्युत विभाग को निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए कहा है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलक्टर नेस्वास्थ्य विभाग को परीक्षा केंद्रों के समीप आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रखने, एम्बुलेंस एवं चिकित्सकीय दल की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। परिवहन विभाग को परीक्षार्थियों के सुगम आवागमन के लिए पर्याप्त परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया है। जिला प्रशासन द्वारा सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए परीक्षा को सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं।

एचपीवी टीकाकरण को लेकर अभिभावकों एवं आमजन से अपील

बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु टीकाकरण कराने पर दिया जोर

सामुदायिक प्रेषण

जयपुर। जिले में बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जिला प्रशासन एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभिभावकों एवं आमजन से अपील की गई है कि वे इस महत्वपूर्ण टीकाकरण अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाएं। जिला कलक्टर संदेश नायक ने कहा कि एचपीवी टीका महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए अत्यंत प्रभावी एवं सुरक्षित माना गया है। यह टीका विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणित है तथा क्लिनिकली टेस्टेड होने के साथ पूर्णतः सुरक्षित है। यह टीकाकरण जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एचपीवी टीका एक सिंगल डोज के रूप में लगाया जाता है, जो बालिकाओं के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। टीकाकरण हेतु आधार कार्ड, स्कूल आईडी अथवा अंकतालिका में से कोई एक दस्तावेज आयु प्रमाण के रूप में आवश्यक है। जिन बालिकाओं के पास दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए अभिभावक,संरक्षक द्वारा सहमति पत्र देकर आयु प्रमाणित किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि एचपीवी टीके को लेकर फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों या भ्रामक जानकारियों पर विश्वास न करें। यह टीका सुरक्षित है तथा इसके कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं हैं और यह सर्वाइकल कैंसर से 95 प्रतिशत से अधिक तक बचाव प्रदान करता है। जिला प्रशासन द्वारा अभिभावकों एवं आमजन से अपील की गई है कि वे अपनी बालिकाओं के बेहतर स्वास्थ्य एवं सुरक्षित भविष्य के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर एचपीवी टीकाकरण अवश्य कराएं, ताकि उन्हें गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखा जा सके।

नीट परीक्षा 2026 में अनुचित साधनों का उपयोग करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही,

परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश

सामुदायिक प्रेषण

जयपुर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित नीट (यूजी) परीक्षा 2026 के निष्पक्ष एवं पारदर्शी आयोजन को सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन जयपुर द्वारा अनुचित साधनों एवं परीक्षा नियमों के उल्लंघन पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जयपुर शहर के परीक्षा कोऑर्डिनेटर महिपाल सिंह ने बताया कि परीक्षा से पूर्व, दौरान या पश्चात किसी भी स्तर पर अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को अनुचित साधनों का प्रयोग (यूएफएम) का दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को एनटीए परीक्षाओं से अधिकतम 3 वर्ष तक प्रतिबंधित किया जा सकता है तथा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही भी की जाएगी। निर्देशानुसार अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों का नीट (यूजी)-2026 का परिणाम निरस्त किया जाएगा। साथ ही गलत परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने, अन्य अभ्यर्थी की ओएमआर शीट/प्रश्न पुस्तिका पर लिखने या लिखवाने की स्थिति में भी परिणाम रद्द किया जाएगा। परीक्षा अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि अनुचित साधनों के मामलों में दोषी अभ्यर्थी को नई ओएमआर शीट या प्रश्न पुस्तिका प्रदान नहीं की जाएगी तथा वह उसी ओएमआर शीट पर परीक्षा जारी रखेगा। घटना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी एवं निरीक्षकों के बयान तथा घटना का समय दर्ज किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी बयान देने से मना करता है, तो उसे बाध्य नहीं किया जाएगा एवं इस तथ्य को रिकॉर्ड किया जाएगा। ओएमआर शीट पर इस संबंध में कोई टिप्पणी अंकित नहीं की जाएगी तथा संपूर्ण रिपोर्ट निर्धारित पीले लिफाफे में सुरक्षित रखी जाएगी। निरीक्षक एवं अधीक्षक के बयानों में घटना का समय, अनुचित सामग्री का स्रोत, सामग्री जब्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर तथा प्रत्येक पृष्ठ पर अधीक्षक के काउंटर सिग्नेचर अनिवार्य रूप से दर्ज किए जाएंगे। ओएमआर शीट,उत्तर पुस्तिका को परीक्षा केंद्र से बाहर ले जाने के प्रयास की स्थिति में अभ्यर्थी से शीट वापस ले ली जाएगी। शीट वापस लेने में असफल होने पर तत्काल पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी, जिसकी प्रति एनटीए को प्रेषित की जाएगी तथा संबंधित निरीक्षकों, अभ्यर्थी एवं अन्य कार्मिकों के बयान संलग्न किए जाएंगे। प्रतिरूपण के मामलों में नकली अभ्यर्थी को तत्काल पुलिस के हवाले किया जाएगा एवं एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वास्तविक एवं नकली दोनों अभ्यर्थियों के बयान लिए जाएंगे तथा प्रेक्षक को गवाह के रूप में शामिल किया जाएगा। गंभीर अनुशासनहीनता के मामलों में पुलिस को तत्काल सूचित करना अनिवार्य किया गया है तथा सभी संबंधित व्यक्तियों के बयान संकलित कर एनटीए को भेजे जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा अधीक्षक द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही या कर्तव्य में चूक पाए जाने पर जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा कठोर कार्यवाही की संस्तुति की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी परीक्षा की शुचिता बनाए रखने हेतु प्रत्येक स्तर पर सतर्कता बरतने पर बल दिया गया है।

जनगणना के प्रथम चरण में स्व-गणना का कार्य 1 मई से 15 मई तक

पार्टल के माध्यम से डेक्सटोप अथवा स्मार्टफोन पर कर सकेंगे स्व-गणना

तैयारिया पूर्ण, जिला कलक्टर ने जिलेवासियो से की स्व-गणना की अपील

सामुदायिक प्रेषण

जयपुर। जयपुर जिले में जनगणना के प्रथम चरण स्व-गणना का कार्य 1 मई से प्रारम्भ होकर 15 मई तक चलेगा। इसके लिए अधिकृत पार्टल http//se.census.gov.in पर जाकर परिवार का मुखिया या कोई भी एक सदस्य जानकारी अपलोड कर सकेगा। ओटीपी किसी को भी शेयर नहीं करें। प्रगणक को भी नहीं, जब वह डेटा सत्यापन के लिए आए। स्व-गणना पोर्टल 1 मई से प्रारम्भ होकर 15 मई के बीच खुला रहेगा। प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं जिला कलक्टर संदेश नायक ने बताया कि स्व-गणना का पोर्टल का उपयोग डेस्कटॉप अथवा स्मार्टफोन पर किया जा सकता है। स्व-गणना के बाद भी प्रगणक व्यक्ति के घर जाकर सत्यापन एवं डाटा की जांच करेगे। स्व-गणना मे डेटा अंकित करने के बाद प्री-व्यू दिखाई देगा। यदि परिवार का मुख्या या सदस्य डाटा में कुछ एडिट करना चाहता है तो ऑप्षन पर जाकर कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद डाटा एडिट नहीं होगा, लेकिन जब प्रगणक डेटा जांच के लिए आएंगे तो आप अपनी सूचना एडिट करा सकेंगे। जयपुर जिले में आगामी जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानो की गणना सफल आयोजन हेतु प्रशासन द्वारा चरणबद्ध तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। जिले के किशनपोल जोन (नगर निगम हेरिटेज) के वार्ड संख्या 55, 56 एवं 63 में जनगणना प्री-टेस्ट माह नवम्बर 2025 तक पूर्ण कर लिया गया है। सीमा फ्रीज (सीमा सील) के कार्य के साथ ही प्रशासनिक इकाइयों की सूची एवं मानचित्रों का सत्यापन भी 31 दिसंबर 2025 तक पूर्ण कर लिया गया है। उन्होने बताया कि जनगणना कार्य के सुचारु संचालन के लिए जिला एवं चार्ज स्तर पर जनगणना सेल का गठन कर दिया गया है। जिले में कुल 5277 गणना ब्लॉकों का गठन किया गया है, जिनके लिए 4779 प्रगणक एवं 780 सुपरवाईजर की नियुक्ति की गई है। जनगणना से संबंधित विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी सफलतापूर्वक संपन्न करा लिया गया है। अधिसूचना प्रकाशन 22 जनवरी, 2026 (मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना) जिला स्तरीय प्रशिक्षण-प्रथम चरण जिला, उप जिला जनगणना अधिकारी, डीओआईटी अधिकारी, चार्ज अधिकारी एवं तहसीलदार, अति. चार्ज अधिकारी एवं नायब तहसीलदार का प्रशिक्षण 10 से 11 फरवरी 2026, नियमित सहायकों का, जिलाध्चार्ज स्तर पर जनगणना सेल में नियुक्त कार्मिको का प्रशिक्षण 16 से 18 फरवरी 2026 व चार्ज अधिकारी एवं आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी नगर परिषद्, पालिका व अतिरिक्त चार्ज अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों का प्रशिक्षण 19 से 20 फरवरी 2026 को पूर्ण किया जा चुका है। जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (सीएमएमएस) पर सभी आवश्यक कार्य जैसे आईडी मैपिंग, ब्लॉक निर्माण, प्रशिक्षकों एवं कार्मिकों की सूची तैयार करना आदि पूर्ण कर लिए गए हैं। आगामी चरण में मकान सूचीकरण एवं भवन गणना का कार्य 16 मई से 14 जून 2026 तक प्रस्तावित है। इसके पश्चात द्वितीय चरण में वास्तविक जनसंख्या गणना का कार्य फरवरी 2027 में किया जाएगा। जिला कलक्टर ने जनगणना के प्रथम चरण में 1 से 15 मई 2026 तक आयोजित होने वाले मकान सूचीकरण एवं मकानों के स्व-गणना के कार्य को सभी जिला स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूर्ण गंभीरता व निष्ठा से करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों व आमजन को भी स्वगणना हेतु प्रेरित करने व स्व-जनगणना पोर्टल का अधिकतम उपयोग करने के लिए कहा है।

रीको औद्योगिक क्षेत्र बिचून को पुनः शुरू कराने हेतु जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा

सामुदायिक प्रेषण

जयपुर। ग्राम बिचून एवं आसपास क्षेत्र के नागरिकों ने रीको औद्योगिक क्षेत्र बिचून के कार्यों को पुनः शुरू कराने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर जयपुर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र से क्षेत्र के हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलने के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा। स्थानीय नागरिक इस परियोजना के पक्ष में हैं और इसे क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। हालांकि, कुछ समय से धार्मिक स्थल से जुड़े विवाद के चलते कार्य बाधित हो गया है, जिससे विकास कार्य रुक गया है और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों ने प्रशासन से आग्रह किया कि आस्था और विकास के बीच संतुलन बनाते हुए संबंधित पक्षों से वार्ता कर समाधान निकाला जाए। ज्ञापन में मांग की गई कि आपसी सहमति के आधार पर रीको औद्योगिक क्षेत्र के कार्यों को शीघ्र पुनः शुरू कराया जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को रोजगार एवं सुविधाओं का लाभ मिल सके।

मेहंदी-संगीत की रौनक के बीच शुरू हुआ सामूहिक विवाह महोत्सव

सामूहिक विवाह महोत्सव में सजी मेहंदी-संगीत की रंगत, आज होंगी वैदिक विधि से शादियां

सामुदायिक प्रेषण

कोटा। सामाजिक सरोकारों की दिशा में सराहनीय पहल करते हुए आध्या सेवार्थ फाउंडेशन के तत्वावधान में प्रथम सनाढ्य आदिगौड़ सामूहिक निःशुल्क कन्या विवाह महोत्सव का शुभारंभ 30 अप्रैल को हर्षोल्लास के साथ हुआ। दो दिवसीय इस आयोजन में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ सभी वैवाहिक रस्में संपन्न की जा रही हैं। संस्था के मुख्य संयोजक लोकेश शर्मा ने बताया कि गुरुवार को आयोजित हल्दी-मेहंदी एवं संगीत कार्यक्रम में उत्सव का माहौल देखते ही बन रहा था। दुल्हनों के हाथों में सजी मेहंदी की गहरी रंगत और उसमें रचा अपने जीवनसाथी का नाम, उनके चेहरे की मुस्कान को और भी खास बना रहा था। कोषाध्यक्ष प्रियांशु शर्मा ने बताया कि परिजनों और सखियों ने पारंपरिक गीतों पर झूमकर माहौल को उल्लासमय बना दिया। ढोलक की थाप पर गूंजते मंगल गीतों के बीच दुल्हनें और परिजन खुशी से सराबोर नजर आए। संगीत संध्या में रंग-बिरंगे परिधानों में सजे युवक-युवतियों ने नृत्य प्रस्तुत कर आयोजन में चार चांद लगा दिए एवं अध्यक्ष शालू शर्मा ने बताया कि इस आयोजन में 8 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न होगा। 1 मई को प्रातः 8 बजे निकासी, 10 बजे तोरण, 11 बजे आशीर्वाद समारोह, दोपहर 1 बजे पाणिग्रहण संस्कार तथा 3 बजे विदाई समारोह आयोजित होंगे। इस अवसर पर ओमप्रकाश टंकारिया, रामस्वरूप शर्मा, प्रेम शास्त्री, मनीष तिवारी, भीष्म कुमार शर्मा, गजेन्द्र जोशी, प्रमोद शर्मा, महावीर पंचोली, विजय भारद्वाज, रघुवर दयाल शर्मा, जितेंद्र शर्मा, सतीश शर्मा, प्रियांशु शर्मा सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे।

अति.जिला कलेक्टर एवं अति . जिला मजिस्ट्रेट प्रथम ,विनीता सिंह को दिया ज्ञापन गया

गौ माता को 'राष्ट्रीय माता 'घोषित करने की मांग

सामुदायिक प्रेषण

दिनेश कुमार प्रजापत/सांगानेर (निस)।विप्र सेना संगठन द्वारा जयपुर में जिला कलेक्टर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में गौ माता को 'राष्ट्रीय माता' घोषित करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। ज्ञापन में संगठन ने देशभर में गौ वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की अपील की है। साथ ही गौ तस्करी में लिप्त लोगों के खिलाफ आजीवन कारावास जैसी कठोर सजा का प्रावधान करने की मांग की गई है। विप्र सेना ने यह भी सुझाव दिया कि मवेशियों की तस्करी में उपयोग किए जाने वाले वाहनों को स्थायी रूप से जब्त कर उनकी नीलामी की जाए, ताकि इस अवैध गतिविधि पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। इसके अतिरिक्त, संगठन ने पशु मेलों के नाम पर होने वाली अवैध तस्करी को रोकने के लिए केंद्र सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग भी रखी। विप्र सेना जयपुर शहर अध्यक्ष अजीत कुमार शर्मा के नेतृत्व में सौंपा गया। इस दौरान कलेक्ट्री बार एसोसिएशन अध्यक्ष संदीप शर्मा, विप्र सेना विद्याधर नगर अध्यक्ष रविकांत गौड़, अधिवक्ता विनोद दीक्षित एवं अधिवक्ता सुभाष शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। विप्र सेना ने आशा व्यक्त की है कि केंद्र सरकार इस विषय की गंभीरता को समझते हुए शीघ्र उचित निर्णय लेगी।

ग्राम रथ अभियान लोक कला, डिजिटल प्रस्तुति और जनसंवाद से योजनाओं की मिल रही उपयोगी जानकारी

सामुदायिक प्रेषण

श्रीगंगानगर, । राजस्थान सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीण अंचलों तक प्रभावी रूप से पहुँचाने के उद्देश्य से जिले में संचालित ग्राम रथ अभियान के तहत गुरुवार को विभिन्न ग्राम पंचायतों में उत्साहपूर्ण और आकर्षक कार्यक्रम हुए। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए योजनाओं की जानकारी लेने के साथ-साथ इनका लाभ भी लिया जा रहा है। गुरूवार को रायसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र के 43 पीएस, 75 एनपी, बरूवाला, 22 पीटीडी-बी, 6/8 एलपीएम, 2 एलपीएम, समेजा, सूरतगढ़ विधानसभा के सरदारगढ़, 8 एसएचपीडी, सादकवाला, 2 एसएचपीडी-ए, श्रीकरणपुर विधानसभा के 42 एच, रडेवाला, 9 एफए माझीवाला, 2 एफसी मुकन, 61 एफ, अनूपगढ़ विधानसभा के 74 जीबी, 68/2 जीबी, 72 जीबी, 65 जीबी, 61 जीबी, 59 जीबी, श्रीगंगानगर विधानसभा के गणेशगढ़, 9 एमएल, महियावाली, सादुलशहर विधानसभा के अलीपुरा, पतली व गदरखेड़ा गांवों में एलईडी वैन के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया। इन गांवों में ग्राम रथ पहुँचते ही ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला और कार्यक्रम स्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान 13 विभागों की प्रमुख योजनाओं का डिजिटल माध्यम से जीवंत प्रसारण किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का संदेश भी ग्रामीणों को सुनाया गया, जिसमें उन्होंने आमजन से योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में स्थानीय लोक कलाकारों ने गीत, भजन और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से योजनाओं की जानकारी को रोचक अंदाज में प्रस्तुत किया। कलाकारों की प्रभावशाली प्रस्तुतियों ने जहां ग्रामीणों का मनोरंजन किया, वहीं योजनाओं के लाभ और आवेदन प्रक्रिया को भी सरल भाषा में समझाया। विभागीय अधिकारियों ने मौके पर उपस्थित ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित मार्गदर्शिका एवं प्रचार सामग्री वितरित कर उन्हें जागरूक किया। ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम रथ के साथ विशेष सुझाव पेटिका भी रखी गई, जिसमें ग्रामीणों ने अपने सुझाव और फीडबैक दर्ज कराए। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुँचाकर उसे लाभ से जोड़ना है। ग्राम रथ अभियान के तहत कृषि, उद्यानिकी, कृषि विपणन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, सहकारिता, जल संसाधन, उद्योग, ऊर्जा, राजस्व, पंचायती राज, ग्रामीण विकास विभाग की सहभागिता से कृषकों एवं पशुपालकों सहित ग्रामीणों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रथ में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से योजनाओं की ऑडियो, वीडियो प्रस्तुति की व्यवस्था की गई है।

बिजली कटौती होने से आमजन परेशान

सामुदायिक प्रेषण

रमेश जांगिड उनियारा,टोंक । अलीगढ़ कस्बे में लोड़सेटिंग व मेन्टीनेस के नाम से की जा रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर कस्बेवासी काफी परेशान है। बिजली कटौती से आमजन को भीषण गर्मी के चलते जीना मुहाल हो गया है। जिससे आमजन में निगम के अभियंताओं के प्रति रोष व्याप्त है। कस्बेवासियों ने कहा कि विद्युत विभाग की अनदेखी के चलते की जा रही अघोषित बिजली कटौती से कई लघु उद्योग धन्धे चौपट हो रहे है। वही पेयजल आपूर्ति व्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। कस्बे में प्रतिदिन लोड़सेटिंग व मेन्टीनेस के नाम से घण्टो बिजली कटौती से आमजन का बुरा हाल है। लोगों का कहना है कि जयपुर विद्युत वितरण निगम विभाग के अभियंताओं की मनमानी के चलते कस्बे में प्रतिदिन सुबह-शाम व दोपहर के समय घण्टों तथा रात के समय अघोषित बिजली कटोती की जा रही है। रात के समय अघोषित बिजली कटौती के चलते लोगों की नींद हराम हो रही है। वही बिजली कटोती तय नही होने से यह पता नही चलता की कब बिजली आ जाए ओर कब गुल हो जाए।

ग्राम रथ अभियान 1 मई को छः विधानसभा क्षेत्रों के गांवो में जायेंगे प्रचार रथ

सामुदायिक प्रेषण

श्रीगंगानगर, । राज्य सरकार के निर्देशानुसार कृषक, पशुपालकों और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए ग्राम रथ अभियान द्वारा जिले की छः विधानसभाओं में एलईडी वैन द्वारा विभिन्न गांवों में जाकर राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी दी जा रही है। शुक्रवार को इन गांवों में पहुंचेगा प्रचार रथ जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव ने बताया कि 1 मई को रायसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र के मोकमवाला, 6 पीटीडी-बी, 68 एनपी, भोमपुरा, बगीचा, श्यामगढ़, सूरतगढ़ विधानसभा के 17 एसटीबी, 4 केएसआर, रामसरा जाखडान, संघर, श्रीकरणपुर विधानसभा के 2 एफएफए, मोटासरखूनी, 56 एफ, 50 एफ रूपनगर, 9 एफएफ बड़ोपल, अनूपगढ़ विधानसभा के 54 जीबी, 4 केएएम, 3 एनडी, 4 ए, 2 पीजीएम बी, 12 एबी, श्रीगंगानगर विधानसभा के 8 एचएच, 4 एलएल, 5 एलएल, सादुलशहर विधानसभा के खाटसजवार, प्रतापपुरा व बहरामपुरा बोदला गांवों में एलईडी वैन के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जायेगा। इसी प्रकार 2 मई को रायसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र के सरदारपुराबीका, सतजण्डा, नानूवाला, 40 एनपी, ठण्डी, सूरतगढ़ विधानसभा के 7 एसजीएम, 28 पीबीएन, भगवानसर, मानकसर, श्रीकरणपुर विधानसभा के 13 एफएफ मानकसर, 52 जीजी, 48 जीजी श्रीनगर, 2 एमएम धरिंगावाली, अनूपगढ़ विधानसभा के 4 एलएम, 6 एनडी, 11/12 एनडी, 3 एनएम, 20 एलएम, 15 एलएम, 9 एलएम बी, श्रीगंगानगर विधानसभा के 21 जीजी, 18 जीजी, 5 जी, 4 जैड, सादुलशहर विधानसभा के मन्नीवाली, छापांवाली व किलांवाली गांवों में एलईडी वैन के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

महियांवाली में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता कार्यशाला आयोजित

सामुदायिक प्रेषण

श्रीगंगानगर, । जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव एवं जिला पुलिस अधीक्षक श्री हरीशंकर के नेतृत्व में जारी नशा मुक्त श्रीगंगानगर अभियान के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महियांवाली में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के श्री विक्रम ज्याणी ने कहा कि नशा करने से पहले एक बार अपनी मां का चेहरा याद कर लेना, तुम्हें खुद ही जवाब मिल जाएगा कि क्या करना है। उन्होंने कहा कि जब आप अपने मां-बाप को अपने कर्मों से खुश करते हैं, तभी असली जीत होती है। इस दौरान साइबर सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के लिए युवाओं को जागरूक किया गया। भारत सरकार की ओर से जारी मानस हेल्पलाइन 1933 की जानकारी देते हुए बताया कि कैसे आप इससे मदद ले सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं। प्रिंसिपल श्रीमती पूनम बंसल ने भी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और उनका सही मार्ग पर चलना पूरे समाज की जिम्मेदारी है। नशा न केवल एक व्यक्ति को बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। कार्यशाला के दौरान विद्यार्थियों ने नशा मुक्ति की शपथ ली और संकल्प किया कि वे स्वयं भी नशे से दूर रहेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे।

प्रदेश के शिक्षको में बढ़ती जा रही नाराजगी.

सामुदायिक प्रेषण

सरकारी विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश में कटौती से बढ़ी नाराजगी इस बार ग्रीष्मावकाश में की गई 10 दिनों की कटौती सभी राजकीय महाविद्यालयों में घोषित किया गया ग्रीष्मावकाश 1 मई से 30 जून तक घोषित किया गया ग्रीष्मावकाश अब शिक्षक नेता पूछ रहे विभाग से सवाल क्या छोटे नौनिहालों को नहीं लगती है गर्मी महाविद्यालय और विद्यालयों के विद्यार्थियों में इतना फर्क क्यों अब और पुरजोर तरीके से विरोध करने का लिया गया निर्णय

ग्राम विकास रथ अभियानकृषि विभाग की डिग्गी निर्माण योजना से लाभान्वित हुए गुरराज

सामुदायिक प्रेषण

श्रीगंगानगर, । माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार जन कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिले में जारी ग्राम विकास रथ अभियान के अंतर्गत पंचायत समिति करणपुर ग्राम पंचायत 2 डब्ल्यू गुरूसर में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। इस दौरान 2 डब्ल्यू गुरूसर निवासी श्री गुरराज सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह ने बताया कि कृषि विभाग की योजना के तहत चक 1 डब्ल्यू में डिग्गी निर्माण कर 3 लाख रूपये अनुदान प्राप्त किया। इससे उन्हें डिग्गी में पानी एकत्रित करके सयम पर फसल को सिंचित करने में आसानी हुई। उन्होंने बताया कि इससे पहले खेत को समय पर सिंचाई नहीं कर पाता था। डिग्गी निर्माण के बाद अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ, जिससे उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई। योजना का लाभ मिलने पर उन्होंने मुख्यमंत्री एवं राजस्थान सरकार का आभार जताया।

ग्राम विकास रथ अभियान करणपुर की करतार कौर को मिला पशु बीमा योजना का लाभ

सामुदायिक प्रेषण

श्रीगंगानगर, । माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार जिले में आयोजित हो रहे ग्राम विकास रथ अभियान ग्रामीणों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। इस अभियान में जहां एक ओर ग्रामीणों सहित आमजन को केन्द्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो रही है, वहीं दूसरी ओर उन्हें इन योजनाओं का मौके पर ही लाभ मिल रहा है। लाभ मिलने पर लाभार्थियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार का आभार जताया जा रहा है। पंचायत समिति श्रीकरणपुर की ग्राम पंचायत 14 एस मांझीवाला में ग्राम रथ अभियान के दौरान श्रीमती करतार सिंह कौर पत्नी श्री कुलविन्द्र सिंह ने बताया कि पशु बीमा योजना के अंतर्गत पशुओं का ईलाज निःशुल्क करवाने में सहायता राशि मिली। उन्होंने बताया कि योजना के तहत बीमार पशुओं का निःशुल्क ईलाज हुआ। अब पशु पूर्णतः स्वस्थ हैं। योजना का लाभ मिलने पर लाभार्थी द्वारा राजस्थान सरकार और माननीय मुख्यमन्त्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया।

ग्राम विकास रथ अभियान मांझीवाला के राजेन्द्र के लिये वरदान बनी एनएफएसएम योजना

सामुदायिक प्रेषण

श्रीगंगानगर, । माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार जिले में आयोजित हो रहे ग्राम विकास रथ अभियान ग्रामीणों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। इस अभियान में जहां एक ओर ग्रामीणों सहित आमजन को केन्द्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो रही है, वहीं दूसरी ओर उन्हें इन योजनाओं का मौके पर ही लाभ मिल रहा है। लाभार्थियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार का आभार जताया जा रहा है। पंचायत समिति श्रीकरणपुर की ग्राम पंचायत 14 एस मांझीवाला में आयोजित ग्राम रथ अभियान के दौरान 14 एस निवासी श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह ने एनएफएसएम/एसएमएएम योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र के लिये अनुदान राशि 2 लाख रूपये प्राप्त की। इससे श्री राजेन्द्र को अपने कृषि कार्य में आसानी हुई, जिससे फसल पैदावार में वृद्धि हुई। इस योजना का लाभ मिलने पर उन्होंने सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया।

ग्राम विकास रथ अभियान प्रधानमंत्री आवास योजना में रसपिन्द्र को मिला पक्का आवास

सामुदायिक प्रेषण

श्रीगंगानगर, । माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार जिले में जनकल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जारी ग्राम विकास रथ अभियान के अंतर्गत पंचायत समिति करणपुर ग्राम पंचायत 2 डब्ल्यू गुरूसर में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। अभियान के दौरान श्री रसपिन्द्र सिंह पुत्र श्री रूप सिंह ने बताया कि उसे अपनी पत्नी श्रीमती अमनदीप कौर के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। पूर्व में उसका मकान कच्चा था लेकिन केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान निर्माण का लाभ मिला। उन्होंने और उनके परिवार ने योजना का लाभ मिलने पर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया

एसएमएएम योजना से मिला अनुदान, पशुपालन हुआ आसान

सामुदायिक प्रेषण

श्रीगंगानगर, । माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार जिले में आयोजित हो रहे ग्राम रथ अभियान ग्रामीणों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। इस अभियान में जहां एक ओर ग्रामीणों सहित आमजन को केन्द्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो रही है, वहीं दूसरी ओर उन्हें इन योजनाओं का मौके पर ही लाभ मिल रहा है। लाभ मिलने पर लाभार्थियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार का आभार जताया जा रहा है। पंचायत समिति सादुलशहर के गांव अलीपुरा में गुरूवार को ग्राम रथ के माध्यम से राज्य सरकार की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को देते हुए योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत निवासी श्री जगदीश चन्द्र पुत्र श्री बनवारी लाल को सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (एसएमएएम) योजना के तहत चारा कटाई मशीन का अनुदान मिला। इसकी सहायता से श्री जगदीश चन्द्र का पशुपालन का कार्य आसान होने से उन्हें लाभ हुआ। इसके लिये लाभार्थी ने माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया

पीएम के भाई प्रह्लाद मोदी पधारे शेखावाटी विवि, कुलगुरु से की विभिन्न मुद्दों पर चर्चा

शैलेंद्रनाथ अघोरी बाबा को मानद उपाधि देने पर जताई प्रसन्नता

सामुदायिक प्रेषण

सीकर, । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी का राजस्थान के निजी प्रवास के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में अनौपचारिक आगमन हुआ। कुलगुरु निवास पर भेंट के दौरान प्रहलाद मोदी ने दीक्षांत समारोह में अघोरी परम्परा के सिद्ध पुरुष शैलेंद्रनाथ महाराज को विवि की ओर से मानद उपाधि प्रदान करने पर प्रसन्नता जताई और कहा कि यह सनातन संस्कृति को प्रतिष्ठित करने की दिशा में महात्वपूण पहल है। विवि शिक्षा और संस्कृति का मुख्य केन्द्र माना जाता है, इसलिए शिक्षा जगत के साथ धर्म और आध्यात्म जगत के अग्रणी महापुरुषों को सम्मानित करना अपनी सनातन परंपरा का सम्मान है। इस अवसर पर शेखावाटी विवि के कुलगुरु प्रो (डॉ.) अनिल कुमार राय ने विश्वविद्यालय द्वारा समाज और राष्ट्रहित में किए जा रहे कार्यों और नवाचारों की जानकारी दी। कुलगुरु ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और उसके दूरदर्शी परिणाम के संदर्भ में चर्चा की। चर्चा में राशन डीलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रहलाद मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि शेखावाटी वीरों और व्यवसायियों की भूमि तो है ही परंतु अब शिक्षा और नवाचार में भी अग्रणी है। पीएम के भाई मोदी ने इस बात पर खुशी जाहिर की शेखावाटी विवि अत्याधुनिक अकादमिक विषयों जैसे एआई–एमएल, साइबर सिक्यूरिटी, फोरेंसिक साइंस, पत्रकारिता एवं जनसंचार जैसे पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है। प्रहलाद मोदी ने कहा कि निःसंदेह यह विवि राजस्थान में शैक्षिक नेतृत्व करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। सनातन संवाद कार्यक्रम करने का सुझाव इस अवसर पर कामाख्या के साधक मुकुंदगढ़ के डॉ शैलेंद्र नाथ अघोरी महाराज भी उपस्थित रहे। डॉ. शैलेंद्र नाथ ने विश्वविद्यालय में युवाओं में आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना विकसित करने की दृष्टि से सनातन संवाद कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया। चर्चा के दौरान प्रहलाद मोदी की सुपुत्री सोनल मोदी और दामाद विराट मोदी के साथ झुंझुनू व सीकर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रहलाद मोदी और डॉ. शैलेंद्र नाथ ने कुलगुरु के परिजनों से बात कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। पीएम के भाई मोदी विश्वविद्यालय की अकादमिक और विकासात्मक संरचना की भव्यता को देखकर काफी प्रभावित हुए तथा इसकी तुलना गुजरात के चुनींदा विकसित निजी विवि से की। कुलगुरु प्रो (डॉ.) अनिल कुमार राय ने कुलगुरु निवास पर आगंतुकों का स्वागत सम्मान किया।

जनगणना 2027: 1 से 15 मई तक खुद दर्ज कर सकेंगे अपनी जानकारी, कलेक्टर ने की अपील

सामुदायिक प्रेषण

दौसा/रामकेश गुर्जर। देश की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गतिविधि 'जनगणना 2027' का आगाज हो चुका है। जिला कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी डॉ. सौम्या झा ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिले के नागरिकों से इस प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि इस बार आम नागरिकों के लिए 'स्व-गणना' (Self Enumeration) की विशेष सुविधा दी गई है।

15 मई तक 'स्व-गणना' का मौका

जिला कलेक्टर के अनुसार, 1 से 15 मई 2026 तक नागरिक स्वयं अपनी और अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल https//se.census.gov.in पर जाकर दर्ज कर सकते हैं।

SE-ID: स्व-गणना प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्येक परिवार को 11 अंकों की एक 'एसई आईडी' प्राप्त होगी।

प्रगणक को दिखाएं: जब प्रगणक (Enumerator) आपके घर आए, तो उन्हें यह आईडी दिखाना अनिवार्य होगा।

दो चरणों में होगी जनगणना प्रक्रिया

जनगणना 2027 को दो मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है:

प्रथम चरण (16 मई से 14 जून 2026): इस दौरान मकान सूचीकरण (House Listing) और गणना का कार्य किया जाएगा।

द्वितीय चरण (फरवरी 2027): इस चरण में जनसंख्या गणना का मुख्य कार्य पूरा किया जाएगा।

जिले में प्रशासनिक तैयारियाँ पूरी

कलेक्टर ने बताया कि जिले में जनगणना कार्यों के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं:

कार्यबल: जिले में कुल 3157 प्रगणक और 524 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं।

प्रशिक्षण: कार्मिकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 30 अप्रैल से 12 मई तक आयोजित किया जा रहा है।

डिजिटल मैपिंग: सीएमएमएस पोर्टल पर जियो-टैगिंग और डिमार्केशन का कार्य भी पूरा कर लिया गया है।'जनगणना से प्राप्त विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर ही भविष्य की विकास योजनाएं, शिक्षा, आवास और बुनियादी ढांचे का निर्माण होता है। नागरिकों द्वारा दी गई सभी जानकारियां पूर्णतः गोपनीय रखी जाएंगी। ' डॉ. सौम्या झा, जिला कलेक्टर जनगणना क्यों है महत्वपूर्ण इस प्रक्रिया के माध्यम से जनसंख्या की विशेषताओं, आर्थिक गतिविधियों, साक्षरता, शहरीकरण, अनुसूचित जाति-जनजाति, भाषा, धर्म और दिव्यांगता जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं के आंकड़े प्राप्त होते हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और विभिन्न जन कल्याणकारी नीतियों का निर्धारण किया जाता है।

स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 के तहत नगर परिषद का अभियान, प्रतिबंधित प्लास्टिक थैलियों के उपयोग पर की कार्रवाई

सामुदायिक प्रेषण

सीकर, । स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत जिला कलेक्टर आशीष मोदी के आदेशानुसार एवं नगर परिषद सीकर के वरिष्ठ आयुक्त शशिकांत शर्मा के निर्देशानुसार शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक थैलियों के उपयोग पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत अधिशाषी अभियंता नागरमल के नेतृत्व में नगर परिषद की प्रवर्तन दस्ता टीम ने बजाज सर्किल (बजरंग कांटा) क्षेत्र में फल, फ्रूट एवं सब्जी रेहड़ी-ठेला संचालकों को प्लास्टिक थैलियों का उपयोग नहीं करने के लिए समझाइश की। टीम द्वारा सभी विक्रेताओं को पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया गया तथा मक्का के दानों से निर्मित बायोडिग्रेडेबल कम्पोस्ट थैलियों के उपयोग के प्रति जागरूक किया गया। वरिष्ठ आयुक्त शशिकांत शर्मा ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि प्लास्टिक केवल सुविधा नहीं, बल्कि पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। आज लिया गया छोटा सा संकल्प आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकता है। यदि सभी नागरिक दैनिक आदतों में थोड़ा बदलाव लाएं, जैसे बाजार जाते समय कपड़े का थैला साथ रखें, तो मिलकर सीकर को स्वच्छ, सुंदर एवं प्लास्टिक मुक्त शहर बनाया जा सकता है।

जनगणना-2027 का प्रथम चरण कल से प्रारंभ

सामुदायिक प्रेषण

सीकर, । भारत की जनगणना-2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत जिले में स्वगणना कार्य का शुभारंभ 1 मई 2026 से किया जाएगा। इसके तहत नागरिक 1 मई से 15 मई 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपने परिवार एवं मकान संबंधी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके पश्चात 16 मई से 14 जून 2026 तक मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर किया जाएगा। जिला कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी ने बताया कि जनगणना राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर विभिन्न विकास योजनाओं, आधारभूत सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाती है। उन्होंने बताया कि नागरिकों की सुविधा के लिए स्वगणना (सेल्फ इनुमेरेशन) की व्यवस्था ऑनलाइन पोर्टल http//se.census.gov.in पर उपलब्ध कराई गई है। यह सुविधा 1 मई से 15 मई तक रहेगी। नागरिक घर बैठे अपनी सुविधा अनुसार परिवार से संबंधित जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। पोर्टल हिन्दी, अंग्रेजी सहित 14 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। स्वगणना प्रक्रिया पूर्ण होने पर नागरिकों को पहचान संख्या मोबाइल अथवा ई-मेल पर प्राप्त होगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि 16 मई से 14 जून तक प्रशिक्षित प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी एकत्रित करेंगे। इस दौरान स्वगणना करने वाले नागरिकों को सत्यापन हेतु अपनी स्वगणना पहचान संख्या उपलब्ध करानी होगी। जनगणना के दौरान प्राप्त सभी सूचनाएं पूर्णतः सुरक्षित एवं गोपनीय रखी जाएंगी। जनगणना के प्रथम चरण में कुल 33 प्रश्नों के माध्यम से जानकारी एकत्रित की जाएगी, जिनमें मकान संख्या, निर्माण सामग्री, मकान की स्थिति, परिवार के सदस्यों की संख्या, पेयजल स्रोत, प्रकाश व्यवस्था, शौचालय, रसोईघर, ईंधन, इंटरनेट सुविधा, मोबाइल, वाहन, मुख्य अनाज तथा मोबाइल नंबर सहित विभिन्न विवरण शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि जनगणना-2027 में पहली बार डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। डाटा संकलन के लिए प्रगणकों द्वारा मोबाइल एप का उपयोग किया जाएगा, जिससे कार्य की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित होगी। जिला कलेक्टर ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाएं तथा अधिकाधिक संख्या में स्वगणना कर जनगणना कार्य को सफल बनाएं।

ग्राम पंचायत भादवाड़ी में आयोजित रात्रि चौपाल में विशेष योग्यजन पेंशनर को मिली राहत

10 माह से बंद विशेष योग्यजन पेंशन पुनः शुरू, रात्रि चौपाल में मिली राहत

सामुदायिक प्रेषण

सीकर, । उप निदेशक प्रियंका पारीक ने बताया कि खंडेला ब्लॉक की ग्राम पंचायत भादवाड़ी में 29 अप्रैल 2026 को आयोजित रात्रि चौपाल में आए परिवादी मोहम्मद ईरफान पुत्र गन्नी मोहम्मद कुरेशी की विशेष योग्यजन पेंशन भौतिक सत्यापन के अभाव में पिछले 10 माह से बंद थी। प्रकरण संज्ञान में आने के पश्चात जिला कलेक्टर आशीष मोदी के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा परिवादी का भौतिक सत्यापन करवाया गया तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन पुनः प्रारंभ कर दिव्यांगजन को राहत प्रदान की गई। उप निदेशक ने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष योग्यजन पेंशनर्स के वार्षिक भौतिक सत्यापन के संबंध में उपखंड अधिकारियों, विकास अधिकारियों एवं ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे डोर-टू-डोर जाकर शत-प्रतिशत वार्षिक भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करें, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर पेंशन का लाभ मिल सके।

स्थानीय बोली में ग्रामीणों से जन संवाद करने से उनको मिल रही सरकारी की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी

सामुदायिक प्रेषण

सीकर, । राजस्थान सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीण अंचलों तक प्रभावी रूप से पहुँचाने के उद्देश्य से जिले में संचालित ग्राम रथ अभियान के तहत गुरुवार को विभिन्न ग्राम पंचायतों में उत्साहपूर्ण और आकर्षक कार्यक्रम हुए। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए योजनाओं की जानकारी लेने के साथ-साथ इनका लाभ भी लिया जा रहा है। गुरूवार को पंचायत समिति फतेहपुर के खोटिया, पालास, लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के चूडीमिंयान, सांखू, खेडी राडान, रहनावा, ढोलास, धोद क्षेत्र के किरडोली, सांवलोदा धायलान, सांवलोदा पुरोहितान, खाखोली, सीकर क्षेत्र के गुमाना का बास, लक्ष्मणा का बास, रामनगर, कुशलपुरा, सिंहासन, दांतारामगढ़ क्षेत्र के राजपुरा (नौसाल), करड़, चक, कुली, खण्डेला क्षेत्र के चौकड़ी, बासड़ी, पिपलोदा का बास, सुजाना, नीमकाथाना क्षेत्र के ठिकरिया, भगेगा, सिरोही, भूदोली, झिराणा तथा श्रीमाधोपुर क्षेत्र के नांगल, नाथूसर, बागरियावास, मऊ सहित अन्य गांवों में ग्राम रथ द्वारा एलईडी वैन के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया। इन गांवों में ग्राम रथ पहुँचते ही ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला और कार्यक्रम स्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान विभागों की प्रमुख योजनाओं का डिजिटल माध्यम से जीवंत प्रसारण किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संदेश भी ग्रामीणों को सुनाया गया, जिसमें उन्होंने आमजन से योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में स्थानीय लोक कलाकारों ने गीत, भजन और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से योजनाओं की जानकारी को रोचक अंदाज में प्रस्तुत किया। कलाकारों की प्रभावशाली प्रस्तुतियों ने जहां ग्रामीणों का मनोरंजन किया, वहीं योजनाओं के लाभ और आवेदन प्रक्रिया को भी सरल भाषा में समझाया। विभागीय अधिकारियों ने मौके पर उपस्थित ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित मार्गदर्शिका एवं प्रचार सामग्री वितरित कर उन्हें जागरूक किया। ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम रथ के साथ विशेष सुझाव पेटिका भी रखी गई, जिसमें ग्रामीणों ने अपने सुझाव और फीडबैक दर्ज कराए। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुँचाकर उसे लाभ से जोड़ना है। ग्राम रथ अभियान के तहत कृषि, उद्यानिकी, कृषि विपणन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, सहकारिता, जल संसाधन, उद्योग, ऊर्जा, राजस्व, पंचायती राज, ग्रामीण विकास विभाग की सहभागिता से कृषकों एवं पशुपालकों सहित ग्रामीणों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रथ में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से योजनाओं की ऑडियो, वीडियो प्रस्तुति की व्यवस्था की गई है।

जिला कलेक्टर ने सैंथल सागर बांध और मनरेगा कार्यों का किया औचक निरीक्षण

सामुदायिक प्रेषण

दौसा / रामकेश गुर्जर। जिला कलेक्टर डॉ. सौम्या झा ने गुरुवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों का सघन दौरा कर विकास कार्यों और जल संसाधनों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सैंथल सागर बांध, ग्राम पंचायत बोरोदा एवं पंचायत समिति दौसा की ग्राम पंचायत रामपुरा उर्फ महाराजपुरा में चल रहे कार्यों का विस्तृत निरीक्षण किया। बांध सुरक्षा और मानसून पूर्व तैयारियों पर जोर कलेक्टर ने सैंथल सागर बांध की वर्तमान स्थिति, जल भराव क्षमता और संरचनात्मक मजबूती का बारीकी से अवलोकन किया। अधिकारियों ने जानकारी दी कि बांध की कुल भराव क्षमता 555.40 एमसीएफटी है, जिससे तीन नहरों के जरिए हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। प्रमुख निर्देशः कलेक्टर ने मानसून से पूर्व सभी आवश्यक मरम्मत और सुदृढ़ीकरण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसी भी संभावित

आपात स्थिति से निपटने के लिए पूर्व तैयारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। ग्राम पंचायतों में विकास योजनाओं की समीक्षा बोरोदा ग्राम पंचायत कार्यालय के निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने पंचायत अभिलेखों की जांच की और ग्राम विकास अधिकारी से विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने नए वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने और कार्यों में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। मनरेगाः *पौधशाला और चरागाह विकास ग्राम पंचायत रामपुरा उर्फ महाराजपुरा में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत विकसित की जा रही पौधशाला और चरागाह क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। वृक्षारोपणः चरागाह विकास के तहत अमरूद, अनार, बेर, जामुन, आंवला जैसे फलदार और नीम, पीपल, मोरिंगा जैसे छायादार कुल 2500 पौधे लगाए गए हैं। नर्सरीः पंचायत नर्सरी में लगभग 5 हजार पौधे तैयार किए गए हैं। विशेष निर्देशः भीषण गर्मी को देखते हुए कलक्टर ने पौधों की नियमित सिंचाई और छाया की व्यवस्था करने को कहा ताकि उनकी जीवितता दर (survival rate) बढ़ाई जा सके। निरीक्षण के दौरान मौजूद अधिकारी इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान सैंथल उपखंड अधिकारी अमृता खंडेलवाल, जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता एमएल मीणा, मनरेगा जिला परिषद के अधिशासी अभियंता सीताराम मीणा, विकास अधिकारी मातादीन मीणा और सहायक अभियंता लोकेश मीणा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

बीमा क्लेम में गड़बड़ी का आरोप, किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

सामुदायिक प्रेषण

टोंक। जिले के किसानों ने फसल बीमा क्लेम में कथित गड़बड़ी को लेकर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन एडीएम टोंक के माध्यम से भेजा गया। किसान नेता रतन खोखर (प्रदेश महासचिव, किसान महापंचायत राजस्थान) ने बताया कि वर्ष 2024-25 में फसल खराब होने के बावजूद बीमा क्लेम राशि केवल कुछ किसानों के खातों में ही जमा की गई, जबकि करीब 70 प्रतिशत किसान इससे वंचित रह गए। इससे किसानों में भारी असंतोष है। उन्होंने कहा कि पहले से ही प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों को योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के चलते किसानों की स्थिति और कमजोर होती जा रही है। किसानों ने मांग की कि टोंक जिले के सभी पात्र किसानों को बिना भेदभाव फसल खराबे का मुआवजा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम दिया जाए। साथ ही क्लेम वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगों का समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे।

पुलिस थाना सुलताना विशेष अभियान म्यूल हंटर के तहत प्रकरण दर्ज कर एक साईबर अपराधी को किया गया गिरफ्तार

सामुदायिक प्रेषण

श्रीमान् महानिदेशक पुलिस साईबर क्राईम एवं तकनीकी सेवाएं राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार साईबर अपराधों की रोकथाम हेतु संदिग्ध बैंक खातों एवं हॉटस्पॉट पर प्रभावी कार्यवाही हेतु विशेष अभियान म्यूल हंटर के तहत, कावेन्द्र सिंह सागर आईपीएस पुलिस अधीक्षक झुंझुनूं के निर्देशन, श्री देवेन्द्रसिंह राजावत,आरपीएस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय झुन्झुनूं के मार्गदर्शन व श्री विकास धींधवाल आरपीएस वृताधिकारी वृत चिडावा के सुपरविजन एवं श्री रविन्द्र कुमार पु.नि थानाधिकारी सुलताना के नेतृत्व मे थाना सुलताना पर विशेष गठित टीम द्वारा साईबर अपराधों में संलिप्त खाताधारक सोहेल को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। कार्यवाही विवरण - सचांलित विशेष अभियान म्यूल हंटर में साईबर अपराधो की रोकथाम के लिये राष्ट्रीय साईबर क्राईम व समन्वय पोर्टल 1930 पर प्राप्त शिकायतो में संदिग्ध बैक खाता नम्बरों की सुची के अनुसार संदिग्ध बैंक खाता को चैक किया गया तो साईबर क्राईम पोर्टल पर उक्त बैंक खाते मे कुल 16 शिकायते पंजीबद्ध है। जिनका बैंक रिकार्ड प्राप्त किया गया। मुल्जिम सोहेल के खाते में उक्त 16 शिकायतों में साईबर क्राईम में संलिप्त होकर साईबर फ्रॉड राशि में से कुल 1,47,158 /- रूपये का साईबर फ्रॉड राशि को अपने खाता मे प्राप्त किया गया। जिस पर प्रकरण दर्ज कर मुल्जिम मो0 सोयल पुत्र श्री मो0 इकबाल जाति लीलगर उम्र 23 साल निवासी वार्ड न0 26 सुलताना, थाना सुलताना जिला झुन्झुनूं (राज0) को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम से पूछताछ जारी है। आरोपी का पीसी रिमाण्ड प्राप्त किया जा रहा।

गिरफ्तार मुल्जिम - मो0 सोयल पुत्र श्री मो0 इकबाल जाति लीलगर उम्र 23 साल निवासी वार्ड न0 26 सुलताना, थाना सुलताना जिला झुन्झुनूं (राज0)

गठित टीम

01 श्री रविन्द्र पु.नि थानाधिकारी थाना सुलताना जिला झुन्झुनू
02 श्री बनवारी लाल सउनि पुलिस थाना सुलताना
03 श्री सीताराम कानि 1472 पुलिस थाना सुलताना

पुलिस थाना सुलताना गावं गोवला में बंद मकान से चोरी करने का आरोपी विक्रम गिरफ्तार

सामुदायिक प्रेषण

कावेन्द्र सिंह सागर आईपीएस जिला पुलिस अधीक्षक झुंझुनूं के निर्देशन, श्री देवेन्द्रसिंह राजावत,आरपीएस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय झुन्झुनूं के मार्गदर्शन, श्री विकास धींधवाल आरपीएस वृताधिकारी वृत चिडावा के सुपरविजन एवं श्री रविन्द्र कुमार पु.नि थानाधिकारी सुलताना के नेतृत्व मे थाना सुलताना पर गठित टीम द्वारा चोरी करने के आरोपी विक्रम को ?गिरफ्तार कर नगद रूपये व चांदी का सामान बरामद किया गया। घटना का विवरण- दिनांक 25.03.2026 को परिवादी विमलेश निवासी गोवला ने रिपोर्ट दी थी कि उसके रिहायशी बंद मकानों से चांदी के आभुषण व नगद रूपये किसी ने चोरी कर लिये जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

कार्यवाही विवरण – प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये एमआईयू टीम से घटनास्थल का निरीक्षण करवाया जाकर घटनास्थल से साक्ष्य संकलन करवाये गये तथा आरोपी की तलाश बाबत टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा आरोपी की तलाश करते हुये आरोपी विक्रम को गिरफ्तार कर आरोपी से 10000 रूपये नगद व चांदी का सामान बरामद किया गया।

गिरफ्तार मुल्जिम – विक्रम पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति मीणा उम्र 23 साल निवासी नगली गुजरान थाना गुढागौडजी

गठित टीम

01 श्री रविन्द्र पु.नि थानाधिकारी थाना सुलताना जिला झुन्झुनू
02 श्री बनवारी लाल सउनि पुलिस थाना सुलताना
03 श्री सीताराम कानि 1472 पुलिस थाना सुलताना
04 श्री स्नेह कानि0 394 पुलिस थाना सुलताना
05 श्री दिनेश कुमार कानि0 1328 पुलिस थाना सुलताना

विधार्थियों का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित

सामुदायिक प्रेषण

लक्ष्मणगढ़ । स्टेशन मार्ग स्थित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 5 व 8 में, ग्रेड प्राप्त करने वाले व कक्षा 10 में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले विधार्थियों का प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। आयोजित कार्यक्रम में जगदीश पारीक, रामावतार पारीक (बठोठवाले), सम्पत चेजारा, पार्षद विनोद गढ़वाल, लोकेश मीणा, विद्यालय समिति के पदाधिकारी जयप्रकाश सरावगी, विद्यालय के व्यवस्थापक पुरुषोत्तम बील बतौर अतिथि मंचस्थ थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से शुरू हुआ, अतिथियों का परिचय प्रधानाचार्य अशोक शर्मा ने दिया जबकि संचालन आचार्या विनीता शर्मा ने किया। कार्यक्रम मेंउत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले विधार्थियों को प्रतीक चिन्ह व मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया ।

जयपुर में अवैध गैस रीफिलिंग पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 35 सिलेंडर जब्त

सामुदायिक प्रेषण

दिनेश कुमार प्रजापत/सांगानेर (निस)। जयपुर में अवैध गैस सिलेंडर रीफिलिंग और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। यह कार्रवाई सांगानेर सदर थाना पुलिस द्वारा डीसीपी राजर्षि राज के निर्देश पर की गई। मामले में दो आरोपियों अजय शर्मा और उसके भाई बिरदीचंद शर्मा के नाम सामने आए हैं, जो एक मकान में अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण कर उन्हें ऊंचे दामों पर बेच रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी घरेलू गैस सिलेंडरों को अवैध तरीके से इकट्ठा कर उनकी रीफिलिंग कर रहे थे और एक सिलेंडर करीब 3000 रुपये में ब्लैक में बेच रहे थे। इससे न केवल उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण हो रहा था, बल्कि बड़े हादसे की आशंका भी बनी हुई थी। यह पूरी कार्रवाई एसीपी भवानी सिंह के सुपरविजन में और सांगानेर सदर थाना प्रभारी अनिल जैमिनी के नेतृत्व में अंजाम दी गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर सिलेंडरों को जब्त किया और आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि इस तरह की अवैध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते ऐसी खतरनाक और गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस की त्वरित कार्रवाई

सब्जी दुकानदार से मारपीट करने वाले 4 आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार

सामुदायिक प्रेषण

दिनेश कुमार प्रजापत/सांगानेर (निस)। जयपुर शहर के जयसिंहपुरा खोर थाना क्षेत्र में सब्जी विक्रेता के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना ने इलाके में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बना दिया था, लेकिन पुलिस की सक्रियता से स्थिति पर जल्द ही नियंत्रण पा लिया गया। पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर श्री करण शर्मा के अनुसार 28 अप्रैल 2026 की शाम को जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र में एक सब्जी दुकानदार और कुछ युवकों के बीच नींबू को लेकर विवाद हो गया। दुकानदार द्वारा उधार में नींबू देने से इनकार करने पर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो जल्द ही

झगड़े में बदल गई। इसके बाद आरोपी युवक दुकान में घुस गए और दुकानदार पप्लू लाल सैनी के साथ लाठी-डंडों से मारपीट कर फरार हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना जयसिंहपुरा खोर में मामला दर्ज कर तुरंत जांच शुरू की गई। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नीरज पाठक के सुपरविजन में तथा सुरेन्द्र सिंह राणावत के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में थानाधिकारी मुकेश कुमार सहित पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया, जिन्होंने तकनीकी एवं मुखबिर तंत्र की सहायता से आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने इलाके में भय का माहौल बनाने के उद्देश्य से इस वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपियों में मोहित शर्मा (29), किशन सैनी (30), अमित सैनी (20) और शैलेन्द्र पांचाल (34) शामिल हैं, जो सभी जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र के निवासी हैं। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वे पहले भी किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल रहे हैं या नहीं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

पाली में कन्या महाविद्यालय भवन का लोकार्पण समारोह बालिका शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान तेजी से अग्रसर

शैक्षणिक संस्थानों के विकास, विस्तार और उन्नयन से सुनिश्चित हो रही सुलभ शिक्षा, हमारे कार्यकाल में सवा लाख युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, एक भी पेपर लीक नहीं - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

सामुदायिक प्रेषण

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बालिका शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार की दूरगामी नीतियों एवं निर्णयों के माध्यम से उच्च शिक्षा तक के स्तर पर आधारभूत संरचनाओं का विकास और विस्तार सुनिश्चित करते हुए बेटियों को सुलभ शिक्षा के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गुरुवार को पाली के रोहट में श्री राजेश्वर भगवान आंजणी माता कन्या गुरुकुल संस्थान द्वारा नवनिर्मित कन्या

महाविद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम तथा कन्या गुरुकुल के 10वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इस दृष्टि से यह कन्या महाविद्यालय बेटियों को शिक्षा देने में अहम भूमिका निभाएगा। इस दौरान शर्मा ने स्थानीय क्षेत्र की जल आवश्यकता की पूर्ति के लिए डीपीआर बनवाने की घोषणा भी की।

24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली— मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 24 जिलों में किसानों को दिन के समय में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। जो वर्ष 2027 तक पूर प्रदेश में उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को निजी क्षेत्र में 6 लाख एवं सरकारी क्षेत्र में 4 लाख रोजगार के लक्ष्य पर कटिबद्ध होकर कार्य कर रही है। लगभग 1 लाख 25 हजार सरकारी पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है और 1 लाख 33 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया में है। वहीं, सवा लाख पदों का भर्ती कैलेंडर भी जारी किया गया है। निजी क्षेत्र में 3 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में पेपरलीक से युवाओं के सपने टूटे, लेकिन हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ।

मेधावी छात्राओं को 43 हजार से अधिक स्कूटियों का वितरण— भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने लगभग ढाई वर्ष के कार्यकाल में 71 नए राजकीय महाविद्यालय खोलने के साथ ही, 185 नए राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का लोकार्पण किया है। जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने पूरे 5 साल में केवल 57 महाविद्यालयों के भवन ही बनवाए थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भवनों के निर्माण, उन्नयन एवं जीर्णोद्धार के लिए 125 करोड़ रुपये स्वीकृत, पीजी स्तर के 50 और यूजी स्तर के 73 महाविद्यालयों में नए विषय प्रारम्भ, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 330 करोड़ रूपये का अनुदान स्वीकृत करने के साथ ही, मेधावी छात्राओं को 43 हजार से अधिक स्कूटियों का वितरण किया है। समारोह में राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने कहा कि महिला शक्ति को बढ़ाने में श्री राजेश्वर भगवान आंजणी माता कन्या गुरूकुल संस्थान का अहम योगदान रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम ने कहा कि गुरूकुल प्राचीन मूल्यों एवं जीवन संस्कारों की शिक्षा के प्रतीक रहे हैं। इस दिशा में यह संस्थान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित कन्या महाविद्यालय के भवन का लोकार्पण किया और आंजणी माता मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की। साथ ही, उन्होंने गुरुकुल की बालिकाओं से बालिका शिक्षा एवं महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में लिए गए निर्णयों एवं योजनाओं पर संवाद किया। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, सांसद पी.पी. चौधरी, लुम्बाराम चौधरी, विधायक हमीर सिंह भायल, जीवाराम चौधरी, अरुण चौधरी, देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना, अन्य जनप्रतिनिधिगण सहित पीठाधीश्वर साध्वी भगवती बाईजी, दयाराम महाराज, पदमाराम महाराज, सुमन सुलभ महाराज एवं बड़ी संख्या में गुरुकुल छात्राएं और आमजन उपस्थित रहे।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक,मुद्रक एवं संपादक ओमप्रकाश जांगिड़ के लिए स्काईटेक प्रिंटर से मुद्रित एवं प्लॉट नंबर 244 श्याम नगर विस्तार सांगानेर से प्रकाशित फोन नंबर 9784657775 सहायक संपादक, धर्म सिंह गुर्जर, सहयोगी संपादक एवं संरक्षक मुकेश कुमार टेलर पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के लिए जिम्मेदार ईमेल samudayaknews@gamil.com संपादकीय कार्यालय 105, डीपी कार्प ओके प्लस बिल्डिंग, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर

सम्पादकीय

"मानवता सुख शांति प्रेम का, अखिल विश्व में हो
विस्तारस्वतंत्रता का हनन न होवे, रहे सुरक्षित जन अधिकार"

असमय गर्मी के तीखे तेवर

अप्रैल में ही छूटा पसीना, टूटा रिकॉर्ड

मौसम की अपनी गति होती है और उसमें उतार-चढ़ाव की वजहें भी प्रकृति के चक्र का हिस्सा होती हैं। मगर पिछले काफी समय से जिस तरह वैश्विक ताप में बढ़ोतरी की वजह से गर्मी के दिनों में जटिलताएं खड़ी हो रही हैं, वह निश्चित रूप से दुनिया के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। हर वर्ष अप्रैल में गर्मी की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस साल तापमान के जो तेवर दिख रहे हैं, उससे यह साफ है कि मौसम में यह उतार-चढ़ाव सामान्य नहीं है। समूचे उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू की वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है और कई शहरों में तापमान चालीस से बयालीस डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। जिन दिनों लोग मई-जून की तेज गर्मी के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं, उनका शरीर धीरे-धीरे अभ्यस्त हो रहा होता है, उसमें हालत यह है कि चिलचिलाती धूप की वजह से बहुत सारे लोगों के लिए सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है और मौसम विभाग की ओर से सतर्क रहने के लिए चेतावनी जारी करनी पड़ रही है। उसने जो पूर्वानुमान जारी किया, उसके मुताबिक आने वाले कुछ दिनों के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों में मिला-जुला मौसम बना रहेगा, जिसमें कहीं भीषण गर्मी के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ेंगी, तो कहीं थोड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों में लू, उमस भरी गर्मी और गर्म रातों में आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं कुछ इलाकों में आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। मौसम की अपनी गति होती है और उसमें उतार-चढ़ाव की वजहें भी प्रकृति के चक्र का हिस्सा होती हैं। मगर पिछले काफी समय से जिस तरह वैश्विक ताप में बढ़ोतरी की वजह से गर्मी के दिनों में जटिलताएं खड़ी हो रही हैं, वह निश्चित रूप से दुनिया के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दिल्ली में इस गर्मी में अधिकतम तापमान पैंतालीस डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो आमतौर पर मई के उत्तरार्ध और जून में दर्ज किया जाता रहा है। इस वर्ष पश्चिमी विक्षोभ और तूफानों में भी कमी देखी गई, वहीं पिछले अल-नीनो के प्रभाव की वजह से गर्मी में सामान्य से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। अगले दो-तीन दिनों में हल्की बारिश और मौसम में बदलाव का अनुमान है, लेकिन जाहिर है, तापमान में व्यापक उथल-पुथल और लू की आशंकाओं के बीच तेज धूप में निकलने से बचने, पानी पीते रहने और अन्य स्तर पर सावधानी ही बचाव का बेहतर उपाय है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राजधानी दिल्ली में आगामी 29 अप्रैल को तेज आंधी-तूफान संग बारिश की 'पीली चेतावनी' जारी की है। पूरे दिन घने बादल छाए रहने के साथ ही गरज, बिजली व तेज हवाओं संग एक से दो बार बारिश होने की संभावना है।

रक्षा खर्च बढ़ाने की बाध्यता

आज के लोकतांत्रिक युग में किसी देश से यह अपेक्षित नहीं कि वह विस्तारवादी अथवा सामंतवादी मानसिकता का परिचय दे, पर समस्या यह है कि ऐसी मानसिकता वाले देशों की कमी नहीं।

स्टाकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीपरी की इस रिपोर्ट पर आश्चर्य नहीं कि 2025 में विश्व का कुल सैन्य खर्च 2024 के मुकाबले 2.9 प्रतिशत अधिक रहा। अब रक्षा खर्च विश्व की कुल जीडीपी का 2.5 प्रतिशत हो गया है। इस संस्था की रिपोर्ट यह भी बताती है कि रक्षा खर्च में भारत विश्व में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। चूंकि भारत विश्व की चौथी बड़ी सैन्य शक्ति है, इसलिए रक्षा खर्च के मामले में उसका पांचवें स्थान पर होना हैरानी का विषय नहीं। भारत रक्षा खर्च में कटौती इसलिए नहीं कर सकता, क्योंकि चीन और पाकिस्तान जैसे देश उसके लिए समस्या बने हुए हैं। चूंकि वैश्विक परिदृश्य बदलने के साथ लड़ाई के तौर-तरीके भी बदल रहे हैं, इसलिए अपनी सेना के आधुनिकीकरण के चलते भी भारत को रक्षा खर्च बढ़ाना पड़ रहा है। वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए भारत के लिए यह संभव नहीं कि वह अपने रक्षा खर्च में कमी करे। भारत की तरह अन्य कई देशों को भी अपने समक्ष उभर रहे खतरों के कारण अपना रक्षा खर्च बढ़ाना पड़ रहा है। कुछ ऐसे भी देश हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के बाद भी पड़ोसी देशों पर अपना दबदबा कायम करने अथवा उन्हें आतंकित करने के लिए अपना रक्षा खर्च बढ़ाने में जुटे रहते हैं। दुर्भाग्य से पड़ोसी पाकिस्तान ऐसे देशों में प्रमुख है। चीन भी अंधाधुंध तरीके से रक्षा पर खर्च कर रहा है, ताकि एशिया के साथ विश्व में अपना वर्चस्व कायम कर सके। आज के लोकतांत्रिक युग में किसी देश से यह अपेक्षित नहीं कि वह विस्तारवादी अथवा सामंतवादी मानसिकता का परिचय दे, पर समस्या यह है कि ऐसी मानसिकता वाले देशों की कमी नहीं। ऐसे देशों के समक्ष वैश्विक संस्थाएं और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जिस तरह असहाय-निरुपाय है, उसके चलते भी हथियारों की होड़ बढ़ रही है और तमाम देशों को जो पैसा अपने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में खर्च करना चाहिए, वह सैन्य संसाधन जुटाने में खपाना पड़ता है। पिछले कुछ समय से प्रमुख वैश्विक शक्तियां जिस तरह मनमानी कर रही हैं, उससे अभी तक चली आ रही विश्व व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो चुकी है। जैसे यूक्रेन पर रूस का हमला, उसकी मनमानी का परिचायक था, वैसे ही अमेरिका की ओर से पहले वेनेजुएला और फिर ईरान को निशाना बनाना भी उसका मनमानापन ही है। बड़े देशों की यह मनमानी भी रक्षा खर्च की होड़ बढ़ा रही है। भारत चाहकर भी अपना रक्षा खर्च कम नहीं कर सकता, लेकिन उसकी प्राथमिकता अपनी आवश्यकता की अधिकाधिक युद्धक सामग्री का निर्माण देश में ही करना होना चाहिए। इससे देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा और रक्षा खर्च में कमी भी आएगी।

संतुलन पर टिका व्यापार समझौता

अनंत स्वरूप

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए का मूर्त रूप लेना भारत की व्यापारिक कूटनीति में महत्वपूर्ण कदम है। यह इसका भी स्पष्ट संकेत है कि देश पूरे आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंच पर जुड़ाव के लिए तैयार है। भारत अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ और अधिक गहराई से जुड़ने का इच्छुक होने के साथ यह सुनिश्चित करने में भी लगा है उसके किसानों, श्रमिकों, छोटे उद्यमों यानी एमएसएमई और रणनीतिक क्षेत्रों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहें। यह समझौता पिछले वर्ष मार्च में आरंभ हुई वार्ताओं का परिणाम है, जिस पर दिसंबर में ही सहमति बन गई थी और सोमवार को उस पर हस्ताक्षर भी हो गए। यह कवायद आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की दिशा में दोनों पक्षों की प्रबल राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रतीक बनकर भी उभरी है। भारत के लिए यह समझौता केवल इसलिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह एक उच्च आमदनी वाले और व्यापार एकीकृत बाजार में नए अवसर खोलता है, बल्कि इस दृष्टि से भी महत्व रखता है कि इसके माध्यम से भारत के ओशियानिया और प्रशांत क्षेत्र में संबंधों को नया आयाम मिलेगा। अभी भारत और न्यूजीलैंड के बीच 1.3 अरब डालर के द्विपक्षीय व्यापार में भारत को ही बढ़त की स्थिति प्राप्त है, मगर न्यूजीलैंड के 47.5 अरब डालर के आयात में भारत की हिस्सेदारी मात्र दो प्रतिशत के मामूली स्तर पर है। पहले भारतीय उत्पादों पर 10 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगता था, लेकिन एफटीए से ये समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे। व्यापक रूप से देखें तो भारत-न्यूजीलैंड एफटीए भविष्य को ध्यान में रखने वाला समझौता है, जो वस्तुओं और सेवाओं के साथ ही गतिशीलता एवं नवाचार को ध्यान में रखता है। न्यूजीलैंड भारतीय निर्यातों के लिए सभी टैरिफ लाइनों पर निःशुल्क पहुंच प्रदान करने जा रहा है, जिसमें वस्त्र, परिधान, चमड़े के सामान, कालीन, आटोमोबाइल और कलपुर्जों पर ऊंचे टैरिफ समाप्त कर दिए गए हैं। इसके बदले में भारत लगभग 70 प्रतिशत शुल्क श्रेणियों में सीमित बाजार प्रवेश देगा और 30 प्रतिशत श्रेणी में शुल्क तत्काल समाप्त करेगा, जबकि शेष श्रेणियों में इसे चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। भारत ने लगभग 30 प्रतिशत संवेदनशील 'टैरिफ लाइनों' को इस सूची से बाहर रखा है, ताकि घरेलू हितों की रक्षा की जा सके। इसमें डेरी उत्पादों, दालों, चीनी, खाद्य तेल, प्याज, मक्का और बादाम जैसी श्रेणियों को संरक्षण प्रदान किया गया है, जो खाद्य सुरक्षा के साथ ही किसानों के हितों को संबोधित करते हैं। अनूठी विशेषताएं इस एफटीए को और आकर्षण प्रदान करती हैं। जैसे न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डालर के निवेश की बात की है। यह निवेश मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। इसमें एक पुनर्संतुलन का भी प्रविधान है, जो निवेश लक्ष्य पूरे न होने की स्थिति में भारत को उपचारात्मक उपाय करने की अनुमति देता है। यह कदम रोजगार, तकनीक हस्तांतरण और आपूर्ति शृंखला के एकीकरण को बढ़ावा देगा, जिसमें न्यूजीलैंड के मजबूत विदेशी निवेश प्रोफाइल का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, न्यूजीलैंड ओशियानिया-प्रशांत बाजारों और स्थापित वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भारत के लिए एक रणनीतिक प्रवेश-द्वार (गेटवे) की भूमिका भी निभाएगा। भारतीय प्रतिभाओं के लिए भी यह बहुत उपयोगी साबित होने जा रहा है।

समझौते की ताकत इसके संतुलन और आपसी संवेदनाओं की मान्यता में निहित है। भारतीय कृषि क्षेत्र की संवेदनाओं को समझते हुए न्यूजीलैंड कीवी फल, सेब और शहद उत्पादन के लिए कार्य योजनाओं और उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना में भी सहयोग करेगा।

इसमें भारतीय छात्रों के लिए वीजा की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उन्हें पढ़ाई के दौरान 20 घंटे काम करने और पढ़ाई के बाद भी चार साल तक के लिए प्रभावी वीजा दिया जाएगा। न्यूजीलैंड ने किसी एफटीए में पहली बार इस तरह का कोई प्रविधान किया है। एक नई अस्थायी रोजगार प्रवेश श्रेणी के तहत आइटी, स्वास्थ्य सेवा और इंजीनियरिंग क्षेत्र की प्रतिभाओं के लिए 5,000 प्रोफेशनल वीजा भी सुनिश्चित किए गए हैं। इसमें आयुष चिकित्सकों, योग प्रशिक्षकों, भारतीय रसोइयों और संगीत शिक्षकों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए भी तीन साल तक के वीजा का प्रविधान है। ये कदम लोगों के बीच यानी पीटूपी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों यानी बीटूबी संबंधों की काया पलटने की क्षमता रखते हैं। वस्त्र-परिधान क्षेत्र को इस एफटीए से बड़ा संबल मिलने जा रहा है। न्यूजीलैंड हर साल 1.2 अरब डालर के परिधान आयात करता है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी केवल चार प्रतिशत है, जो इस एफटीए के बाद परवान चढ़ती दिखेगी। चमड़ा और फुटवियर के अलावा रत्न एवं आभूषण जैसे क्षेत्र भी इसके बड़े लाभार्थी बनकर उभरेंगे, जहां पूर्ववर्ती टैरिफ भारतीय उत्पादों की संभावनाओं की राह में अवरोध बन रहे थे। इसी तरह इंजीनियरिंग वस्तुओं के 6.6 अरब डालर के बाजार में भारत की जो हिस्सेदारी महज एक प्रतिशत रही, वह भी बढ़ने के भरे-पूरे आसार हैं। फार्मा बाजार में भी भारत की केवल 5.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी को भी एफटीए के बाद और विस्तार मिलेगा। समझौते की ताकत इसके संतुलन और आपसी संवेदनाओं की मान्यता में निहित है। भारतीय कृषि क्षेत्र की संवेदनाओं को समझते हुए न्यूजीलैंड कीवी फल, सेब और शहद उत्पादन के लिए कार्य योजनाओं और उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना में भी सहयोग करेगा।

पंजाब से दिल्ली तक सियासी 'सुनामी' : संकट में आप

भारत की समकालीन राजनीति में शायद ही कोई घटना इतनी तेजी से राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आई हो, जितनी राघव चड्ढा सहित सात राज्यसभा सांसदों के आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से आई है। राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों का भाजपा में विलय केवल एक खबर नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के 15 साल के इतिहास का सबसे बड़ा %ब्लैकआउट% है। भारतीय राजनीति के क्षितिज पर यह घटनाक्रम एक बड़े 'पॉलिटिकल अर्थक्वेक' के रूप में दर्ज हो गया है। आम आदमी पार्टी (आप) के 'पोस्टर बॉय' माने जाने वाले राघव चड्ढा सहित राज्यसभा के 7 सांसदों का एक साथ पाला बदलकर भाजपा में शामिल होना न केवल 'आप' के लिए एक अस्तित्वगत संकट है बल्कि यह देश की राजनीति की दिशा और दशा बदलने वाला घटनाक्रम भी है। यह सिर्फ दल-बदल नहीं बल्कि सत्ता, विचारधारा और राजनीतिक रणनीति के बीच गहरे संघर्ष का संकेत है। जब राज्यसभा में पार्टी के कुल 10 में से 7 सांसद (दो-तिहाई बहुमत) एक साथ अलग होकर भाजपा में विलय करने का निर्णय लेते हैं तो यह दलबदल नहीं, एक वैचारिक और संगठनात्मक विद्रोह का प्रतीक बन जाता है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब भारतीय राजनीति 2027 के बड़े चुनावी चक्र की ओर बढ़ रही है। ऐसे में इस घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या 'आप' का 'पंजाब किला' अब ढहने के कगार पर है? क्या 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव की पटकथा अभी से लिखी जा चुकी है? और सबसे बड़ा प्रश्न कि क्या यह 'आप' के पतन की शुरुआत है या फिर एक अस्थायी राजनीतिक झटका? आम आदमी पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम को केवल राजनीतिक असहमति नहीं बल्कि लोकतंत्र पर सुनियोजित प्रहार करार दिया है। पार्टी नेतृत्व का स्पष्ट आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों के भय, दबाव और राजनीतिक प्रलोभनों के माध्यम से उसके सांसदों को तोड़ा गया, जिसे वह संस्थागत दुरुपयोग की श्रेणी में रखती है। यह आरोप भारतीय राजनीति में सत्ता बनाम विपक्ष की उस पुरानी बहस को फिर जीवित कर देता है, जहां नैतिकता और रणनीति आमने-सामने खड़ी दिखाई देती हैं। संवैधानिक दृष्टि से यह कदम और भी दिलचस्प हो जाता है। दलबदल विरोधी कानून की तकनीकी बारीकी (दो-तिहाई सदस्यों के एक साथ अलग होने की शर्त) का उपयोग करते हुए राघव चड्ढा के नेतृत्व में सात सांसदों का भाजपा में विलय यह संकेत देता है कि यह केवल भावनात्मक निर्णय नहीं बल्कि गहन कानूनी सलाह और रणनीतिक योजना का परिणाम था। सबसे गंभीर आघात वैचारिक स्तर पर है। जब भीतर से ही यह स्वर उठे कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है तो यह केवल संगठनात्मक संकट नहीं बल्कि पहचान के संकट का संकेत बन जाता है और यही चुनौती 'आप' के लिए सबसे कठिन परीक्षा है। पंजाब की राजनीति में उठी यह हलचल महज दल-बदल नहीं बल्कि सत्ता समीकरणों के पुनर्गठन का संकेत है। इस विद्रोह का सबसे गहरा असर पंजाब की सियासत पर पड़ना तय है। राज्यसभा में पंजाब का प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरे (हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, संजीव अरोड़ा और विक्रमजीत सिंह साहनी) का पार्टी से अलग होना 'आप' की उस सामाजिक पकड़ को कमजोर करता है, जो विविध वर्गों के प्रतिनिधित्व से बनी थी। यह बदलाव केवल संख्या का नहीं बल्कि भरोसे और प्रभाव का क्षरण है। सबसे बड़ी चुनौती भगवंत मान के सामने है। यह उनके नेतृत्व और राजनीतिक संतुलन की सीधी परीक्षा है। राघव चड्ढा को लंबे समय तक सरकार और संगठन के बीच रणनीतिक कड़ी माना जाता रहा, उनके हटने से यह संतुलन डगमगाता दिख रहा है। दूसरी ओर, भाजपा इस घटनाक्रम को अवसर में बदलने की कोशिश में है। भाजपा पंजाब में हमेशा से एक %छोटा भाई% (अकाली दल के साथ) बनकर रही है लेकिन 7 सांसदों के आने से, जिनमें सिखों और उद्योगपतियों का प्रतिनिधित्व है, भाजपा अब 2027 में %अकेले दम% पर सरकार बनाने का सपना देख रही है। अब तक सहयोगी राजनीति तक सीमित रही भाजपा अब पंजाब में स्वतंत्र शक्ति बनने की दिशा में आक्रामक कदम बढ़ाती दिख रही है और 2027 का रण अब पहले से कहीं अधिक खुला और अनिश्चित हो गया है। इतिहास गवाह है कि क्षेत्रीय दल जब ऐसे बड़े विद्रोह का सामना करते हैं तो अक्सर वे या तो बिखर जाते हैं या फिर सिमटकर रह जाते हैं लेकिन आप की स्थिति थोड़ी भिन्न है। इसका सबसे बड़ा कारण है अरविंद केजरीवाल का व्यक्तित्व। आम आदमी पार्टी का आधार अरविंद केजरीवाल की 'व्यक्तिगत ब्रांडिंग' पर टिका है। जब तक दिल्ली और पंजाब जैसे अहम राज्यों में उनका जनाधार सुरक्षित है, तब तक 'आप' का पूर्ण पतन लगभग असंभव प्रतीत होता है। इसके समानांतर, 'आप' की ताकत उसका विकसित कैडर ढांचा है। आप ने पिछले एक दशक में एक मजबूत कैडर तैयार किया है। हालांकि शीर्ष स्तर पर योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और अब राघव चड्ढा जैसे प्रमुख चेहरों का अलग होना पार्टी को बड़ा झटका देता है लेकिन जमीनी कार्यकर्ता अब भी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं। एक वैकल्पिक, जनोन्मुख और व्यवस्था-विरोधी नेता की केजरीवाल की छवि अब भी पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी बनी हुई है। राष्ट्रीय राजनीति के व्यापक परिप्रेक्ष्य में यह घटनाक्रम सत्ता-संतुलन को निर्णायक रूप से प्रभावित करता है। राज्यसभा में सात सांसदों के जुड़ने से भाजपा की स्थिति और सुदृढ़ हुई है, जिससे अब महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने में उसकी छोटे दलों पर निर्भर रहने की बाध्यता कम हो गई है। इसके विपरीत, विपक्षी गठबंधन के लिए यह स्पष्ट झटका है क्योंकि 'आप' इस गठबंधन की मुखर आवाज रही है। सबसे गंभीर आघात 'आप' की वैचारिक विश्वसनीयता पर पड़ा है। जो पार्टी 'ईमानदार राजनीति' को अपनी पहचान मानती रही, उसी के भीतर से वैचारिक विचलन और आरोपों का उठना उसके नैरेटिव को कमजोर करता है। यह स्थिति नेतृत्व शैली पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है, लगातार बड़े चेहरों का अलग होना इस ओर संकेत करता है कि संवाद की कमी और निर्णय प्रक्रिया का केंद्रीकरण आंतरिक असंतोष को जन्म दे रहा है। राष्ट्रीय विस्तार की महत्वाकांक्षा पर भी इसका प्रभाव पड़ना तय है। दिल्ली और पंजाब से आगे बढ़ने की जो रणनीति थी, वह अब धीमी पड़नी तय है, विशेषकर तब, जब पंजाब, जो 'आप' का सबसे मजबूत गढ़ है, स्वयं इस राजनीतिक भूकंप के केंद्र में आ खड़ा हुआ है। यह कहना जल्दबाजी होगी कि 7 सांसदों के जाने से आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। राजनीति में रिक्तियां हमेशा भर दी जाती हैं।

आम आदमी पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम को केवल राजनीतिक असहमति नहीं बल्कि लोकतंत्र पर सुनियोजित प्रहार करार दिया है। पार्टी नेतृत्व का स्पष्ट आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों के भय, दबाव और राजनीतिक प्रलोभनों के माध्यम से उसके सांसदों को तोड़ा गया, जिसे वह संस्थागत दुरुपयोग की श्रेणी में रखती है।

महाशक्ति की सुरक्षा में सेंध

ट्रंप पर हमले ने खड़े किए गंभीर सवाल

अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में मीडिया कर्मियों के लिए आयोजित रात्रिभोज में गोलीबारी की घटना ने दुनिया भर में सबके कान खड़े कर दिए हैं। यह वारदात ऐसे मौके पर हुई, जब यहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी एवं प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। हालांकि बाद में सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल है कि विश्व की महाशक्ति होने का दंभ भरने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा में अपने ही देश के भीतर इस तरह की चूक कैसे हो सकती है? कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हमलावर आयोजन स्थल में सेंध लगाने में कैसे कामयाब हो गया! गोलीबारी की वजह से पूरे परिसर में अफरा-तफरी मच गई और ट्रंप को उनकी पत्नी के साथ तत्काल सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ा। यह घटना सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम देशों के लिए भी सबक है, जो मानते हैं कि उनके शीर्ष नेतृत्व की सुरक्षा अभेद्य है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हमलावर ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन यहां राष्ट्रपति की मौजूदगी से मामले की गंभीरता का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप पर पहले भी दो बार हमले हो चुके हैं, हालांकि यह बात अलग है कि उस दौरान वे अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर नहीं थे। मार्च 2016 में लास वेगास में राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार के दौरान रैली में एक व्यक्ति ने मंच के पास पहुंचकर ट्रंप की सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी का हथियार छीनने की कोशिश की थी। हिरासत में पूछताछ में उसने स्वीकार किया था कि वह ट्रंप को नुकसान पहुंचाना चाहता था। इसके बाद जुलाई 2024 में चुनावी रैली में ट्रंप पर उस समय खतरनाक हमला हुआ था, जब वह मंच से भाषण दे रहे थे। मगर गनीमत रही कि हमलावर की ओर से चलाई गई गोली उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छूकर निकल गई। यह बात समझ में आती है कि इन दो घटनाओं के दौरान ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे, इसलिए उनकी सुरक्षा का दायरा उतना बड़ा नहीं था, लेकिन उनके राष्ट्रपति होते हुए अगर सुरक्षा में किसी तरह की चूक होती है, तो व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक है।

परिवर्तन को तैयार दिखता बंगाल

बंगाल सिर्फ वोट नहीं डाल रहा है। वह अपने लोकतांत्रिक भविष्य की नई दिशा भी तय करता दिख रहा है। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के सघन संशोधन का जो अभियान चलाया, उससे राज्य भर से बड़े पैमाने पर संदिग्ध, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया का सख्त और पारदर्शी होना केवल मतदान तक सीमित नहीं है। यह उस औपचारिक राज्य की वापसी है, जो लंबे समय तक स्थानीय शक्ति संरचनाओं के पीछे छिप गया था। मतदाता परिणाम और सुशासन के आधार पर सत्ता की वैधता तय करना चाहता है। राजनीति विज्ञान का एक सीधा नियम है कि जहां अनौपचारिक शक्ति संरचनाएं और सिंडिकेट हावी होते हैं, वहां राज्य की औपचारिक क्षमता पूरी तरह कमजोर हो जाती है। यही स्थिति बंगाल में निवेश और विकास की सबसे बड़ी बाधा बन गई है। जो बंगाल कभी औद्योगिक उत्पादन का प्रमुख केंद्र था, वह आज रोजगार देने में काफी पिछड़ चुका है। जब भी कोई नया कारखाना या उद्यम शुरू होता है, स्थानीय बाहुबली उसमें दखल देते हैं। इससे निवेशक पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। जनता अब ऐसा तंत्र चाहती है, जो पारदर्शी हो और औपचारिक अर्थव्यवस्था को मजबूती दे। यह चुनाव एक गहरे सामाजिक और पीढ़ीगत बदलाव का भी गवाह बन रहा है। नई पीढ़ी राजनीतिक निष्ठा के बजाय अवसरों के आधार पर प्राथमिकताएं तय कर रही है। आज का युवा मतदाता पारंपरिक झंडों और नारों का मोहताज नहीं है। उसे एक ऐसा तंत्र चाहिए जिस पर वह विश्वास कर सके। वह बेंगलुरु, पुणे या दिल्ली जैसी सुविधाओं और अवसरों को अपने ही राज्य में देखना चाहता है। जब यह महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती तो उसका गुस्सा सत्ता के खिलाफ मुखर होता है। राष्ट्रवाद, पारदर्शिता और विकास की राजनीति का जो नया विकल्प राज्य में उभर रहा है, वह इसी युवा वर्ग की आकांक्षाओं को स्वर देता दिख रहा है। राजनीति में नागरिक और सरकार के रिश्ते के मायने भी तेजी से बदल रहे हैं। सरकार की मुफ्त राशन और नकद सहायता जैसी योजनाओं ने समाज के निचले तबके को फौरी राहत जरूर दी है, लेकिन अर्थशास्त्र और राजनीति का यह अनुभव बताता है कि एक सीमा के बाद कल्याणकारी योजनाओं का राजनीतिक प्रभाव घटने लगता है। खासकर तब, जब वे जनता की नई आकांक्षाओं को संतुष्ट नहीं कर पातीं। जब सरकार नागरिकों को स्थायी रूप से केवल 'लाभार्थी' मानकर चलने लगती है तो बुनियादी विकास पीछे छूट जाता है। यह निर्भरता समाज को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देती। बंगाल का मतदाता अब कुछ सौ रुपयों की मासिक सहायता से आगे पक्का रोजगार और अपनी मेहनत का सम्मानजनक मोल चाहता है। सशक्तीकरण का यही माडल अब बंगाल के विमर्श में जगह बनाता प्रतीत हो रहा है। जनसांख्यिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा ऐसी चिंताएं बन चुकी हैं, जिन्हें अब किसी भी कीमत पर अनदेखा नहीं किया जा सकता। सीमावर्ती जिलों में घुसपैठ के आरोप और उनसे जुड़ी चिंताओं ने राज्य की सामाजिक पहचान पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। संदेशखाली जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सत्ता के करीब माने जाने वाले स्थानीय बाहुबलियों ने जिस प्रकार महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई, उसने बंगाली भद्रलोक और ग्रामीण समाज को भीतर तक आहत किया। यह एक विशेष प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति का सीधा नतीजा है। राज्य का एक वर्ग कह रहा है कि इस तरह की नीतियों में कानून के समान शासन की पूरी तरह अनदेखी हो रही है। उत्तर बंगाल के राजबंशी समुदाय से लेकर मतुआ समाज तक, सभी अपनी अस्मिता और अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। बंगाल की राजनीति में लंबे अरसे तक राजनीतिक हिंसा का इस्तेमाल अपना दबदबा बनाए रखने के हथियार के रूप में हुआ है। चुनाव से पहले लोगों को डराना और विरोधियों को निशाना बनाना यहां का कड़वा सच रहा है, लेकिन इस बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भारी तैनाती और चुनाव आयोग के सख्त रवैये ने डर के उस माहौल को काफी हद तक खत्म कर दिया है। इसी सुरक्षित माहौल में बंगाल में एक मौन मतदाता उभर रहा है। यह वह मतदाता है, जो सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहता, लेकिन मतदान केंद्र पर अपनी स्वतंत्र पसंद दर्ज करता है। बिना किसी डर या दबाव के मतदान करने की यह हिम्मत एक परिपक्व होते लोकतंत्र का बहुत शुभ संकेत है। बंगाल की धरती पर चल रहा यह मंथन केवल एक सरकार के कामकाज का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन की पदचाप है। बड़े पैमाने पर संदिग्ध वोटरों के नाम हटना, न्यायपालिका की सख्ती, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और सुशासन की मुखर मांग बता रही है कि राज्य बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जनता के सामने दो रास्ते हैं।

ई-रिक्शा से वोट डालने पहुंचीं महुआ मोइत्रा, बोलीं— लोकतंत्र बचाने की लड़ाई

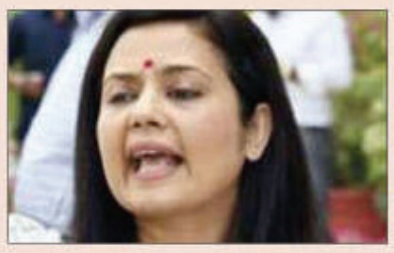

कोलकाता (एजेंसी)। महुआ मोइत्रा ने बुधवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान मतदान कर चुनाव को 'लोकतंत्र बचाने की लड़ाई' बताया। नदिया जिले के करीमपुर गर्ल्स हाई स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर वोट डालने के बाद उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मतदाताओं से बड़ी संख्या में भागीदारी की अपील की। मोइत्रा ई-रिक्शा (टोटो) से मतदान केंद्र पहुंचीं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने उन्हें मोटरसाइकिल से आने की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए उन्हें वैकल्पिक साधन का उपयोग करना पड़ा। मतदान के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। उनके अनुसार, 'करीब 27 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और जो लोग सूची में हैं, वे इस बार 100 प्रतिशत मतदान करेंगे। इसी वजह से मतदान प्रतिशत काफी अधिक रहने वाला है।' उन्होंने आगे कहा कि जनता इस बार 'बदले की भावना' के साथ वोट कर रही है और केंद्र सरकार व चुनाव आयोग को जवाब देगी। मोइत्रा ने इसे सीधे तौर पर लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई बताते हुए कहा कि लोगों में भारी आक्रोश है।

जमानत के बाद भी शिलॉन्ग में ही रहना होगा सोनम रघुवंशी को

शिलांग (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा मोड़ सामने आया है। मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को करीब 320 दिन बाद जमानत मिल गई है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह बिना अनुमति शिलांग नहीं छोड़ सकती और ट्रायल के दौरान वहीं रहना होगा। मेघालय की राजधानी शिलांग की अदालत ने सोमवार को जमानत मंजूर की थी। इसके बाद मंगलवार को उनके पिता देवी सिंह शिलॉन्ग पहुंचे और जमानत की औपचारिकताएं पूरी कीं। मंगलवार शाम को ही सोनम जेल से रिहा भी हो गईं। रिहाई के बाद उन्होंने मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और पिता के साथ वहां से चली गईं। यहां बताते चलें कि यह मामला उस समय चर्चा में आया था जब राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सोनम मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार हुई थीं। अदालत ने चौथी सुनवाई के बाद सोनम को राहत दी है। जमानत का सबसे बड़ा आधार गिरफ्तारी प्रक्रिया में पाई गई खामियां रहीं। बचाव पक्ष ने दलील दी कि 7 जून 2025 को गाजिपुर में गिरफ्तारी के समय आरोपों की स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी। अदालत ने जांच के दस्तावेजों में गंभीर त्रुटियां पाईं और कहा कि यह प्रक्रिया कानून के अनुरूप नहीं थी। कोर्ट ने आर्टिकल 22(1) ऑफ द कॉन्सटिट्यूशन ऑफ इंडिया का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तारी के कारण बताना अनिवार्य है। ऐसा न करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। इसी आधार पर अदालत ने सोनम को जमानत दी, लेकिन सख्त शर्तें भी लगाईं। उन्हें ट्रायल के दौरान शिलॉन्ग में ही रहना होगा और बिना अदालत की अनुमति शहर छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। इस फैसले के बाद मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। अब आगे की सुनवाई और ट्रायल की प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हैं।

भाजपा कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, 16 राउंड फायरिंग से दहशत

पुणे (एजेंसी)। पूना के देहूरोड इलाके में मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात एक सनसनीखेज घटना में भाजपा कार्यकर्ता रमेश रेड्डी की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई और पुलिस ने जांच तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार, रात करीब 9 बजे सवाना चौक पर मौजूद रमेश रेड्डी पर पहले से घात लगाए हमलावरों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने करीब 16 राउंड गोलियां चलाईं, जिनमें से एक गोली उनके सिर में लगी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद देहूरोड क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और परिजन मौके पर पहुंच गए। किसी भी अप्रिय स्थिति को देखते हुए पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है।

भाई की हत्या से जोड़कर देखी जा रही वारदात

मीडिया रिपोर्ट में प्राथमिक जानकारी से खुलासा हुआ है कि रमेश रेड्डी भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता थे। उनका नाम कुछ विवादित गतिविधियों में भी सामने आता रहा है। मटका कारोबार से जुड़े होने की चर्चा भी है, हालांकि फिलहाल यह कारोबार बंद बताया जा रहा है। इस हत्या का संबंध पिछले वर्ष उनके भाई विक्रम गुरुस्वामी रेड्डी की हत्या से भी जोड़ा जा रहा है। विक्रम रेड्डी की मौत जन्मदिन पार्टी के दौरान हुई गोलीबारी में हुई थी। उस मामले में आरोपी अभी जेल में हैं और उन्हें जमानत नहीं मिली है। इसके बावजूद पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है कि क्या किसी समझौते को लेकर विवाद इस नई घटना की वजह बना।

गाजियाबाद की गौर ग्रीन सोसाइटी में भीषण आग

गाजियाबाद (एजेंसी)। ,उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में बुधवार सुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में 9वीं मंजिल से उठी लपटें 13वीं मंजिल तक पहुंच गईं और काले धुएं का गुबार दूर से ही दिखाई देने लगा। आग लगने की सूचना मिलते ही सोसाइटी में अफरा-तफरी मच गई। लोग अपने फ्लैट छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। हालांकि समय रहते राहत एवं बचाव कार्य शुरू होने से बड़ी जनहानि टल गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी को मौके पर पहुंचकर स्थिति की निगरानी करने को कहा गया। दमकल विभाग की करीब 20 गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग बुझाने के साथ ही प्रभावित बिल्डिंग को ठंडा करने का कार्य जारी है। प्रारंभिक जांच में आग 9वीं मंजिल से शुरू होने की बात सामने आई है। आग शॉर्ट सर्किट से लगी या कोई कारण रहा अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है।

राजनाथ का बयान, आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को 'शर्मनाक क्लीन चिट'

अमेरिका के दबाव में पीएम मोदी के इशारे पर दिया गया बयान

नागपुर (एजेंसी)। नई दिल्ली (ईएमएस)। नई दिल्ली में कांग्रेस ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर गंभीर आरोप लगाकर कहा कि उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन (शंघाई सहयोग संगठन) के सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को ÷शर्मनाक क्लीन चिट÷ दे दी। कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि यह रुख प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उस नीति का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका को संतुष्ट करने और चीन के सामने संतुलित समर्पण दिखाने की कोशिश हो रही है।

दरअसल, रक्षा मंत्री सिंह ने एससीओ सम्मेलन में कहा था कि 'ऑपरेशन सिंदूर' भारत के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है और अब आतंकवाद के केंद्रों को सजा से छूट नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की कोई राष्ट्रीयता या धर्म नहीं होता और किसी भी प्रकार की शिकायत—चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक—आतंकवाद को सही ठहराने का आधार नहीं बन सकती।

रक्षा मंत्री सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देकर कांग्रेस नेता रमेश ने आरोप लगाया कि यह बयान प्रधानमंत्री मोदी की स्वीकृति और निर्देश पर दिया गया है और इस बयान से पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष रूप से राहत मिलती है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र नहीं है, क्या वहां भारत के खिलाफ काम करने वाले आतंकी शिविर नहीं हैं, और क्या भारत-विरोधी विचारधारा को वहां बढ़ावा नहीं मिलता है।

कांग्रेस नेता रमेश ने कहा कि मुंबई आतंकी हमला 2008 और पहलगाम से जुड़े आतंकी हमलों की साजिश में भी पाकिस्तान से जुड़े तत्वों की भूमिका रही है।

कांग्रेस नेता ने तुलना की कि यह स्थिति जून 2020 जैसी है, जब भारत-चीन तनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए थे। उनके अनुसार, उस समय भी चीन को ÷क्लीन चिट÷ देने का आरोप लगा था। कुल मिलाकर, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर कमजोर रुख अपनाने का आरोप लगाया है, जबकि मोदी सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

बंगाल चुनाव : बीजेपी के ईवीएम बटन पर टेप लगाया, सुवेंदु चोर के लगे नारे

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण की 142 सीटों पर मतदान जारी है। दोपहर एक बजे तक 61.11फीसदी वोट डाले जा चुके थे। वोटिंग के दौरान कई विधानसभा क्षेत्रों से ईवीएम से छेड़छाड़, मारपीट, झड़प और नारेबाजी की घटनाएं सामने आई। बीजेपी का आरोप है कि डायमंड हार्बर के फाल्टा में ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप लगाकर ब्लॉक किया गया। चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन मतदान केंद्रों पर ईवीएम में काले या सफेद टेप मिलने की शिकायत मिली है, वहां दोबारा चुनाव होंगे।

फाल्टा में सुरक्षाकर्मियों ने हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया। साउथ 24 परगना जिले में बीजेपी उम्मीदवार विकास सरदार ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर उनकी कार का शीशा तोड़ने का आरोप लगाया। उनके सुरक्षाकर्मी की बंदूक छीनने की कोशिश भी की गई। वहीं भवानीपुर में सीएम ममता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी को घेरकर टीएमसी समर्थकों ने चोर-चोर के नारे लगाए। सुवेंदु पोलिंग बूथ का निरीक्षण करने पहुंचे थे। पहले फेज की 152 सीटों पर 23 अप्रैल को रिकॉर्ड 93फीसदी मतदान हुआ है। 4 मई को रिजल्ट आएंगे।

बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा है कि जिन मतदान केंद्रों पर ईवीएम में काले या सफेद टेप मिलने की शिकायत मिली है, वहां दोबारा मतदान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी एक विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में बूथों पर ऐसी शिकायतें सामने आती हैं, तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में ही दोबारा मतदान कराया जाएगा। आरामबाग से टीएमसी सांसद मिताली बाग व्हीलचेयर पर वोट देने पहुंची। 27 अप्रैल को मिताली बाग ने आरोप लगाया था कि चुनाव प्रचार के दौरान उनकी कार पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। घटना के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

लोगों की भीड़ देख साफ हो गया कि पहले चरण का रिकॉर्ड भी टूटेगा

-बीजेपी नेता मिथुन ने डाला वोट कहा-बंगाल में बदलाव की आने वाली है बाढ़

कोलकाता (एजेंसी)। बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में बुधवार को सात जिलों की 142 सीटों पर सुबह से ही मतदान जारी है और आम लोगों से लेकर मंत्री और सांसद भी वोट डालने पहुंच रहे हैं। इसी बीच अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती भी अपना वोट डालने पहुंचे और साफ किया कि इस बार बंगाल में बदलाव की बाढ़ आने वाली है। वोट देने के बाद मिथुन ने विश्वास दिलाया कि चुनाव पूरे निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। वोटिंग शेयर बढ़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो लोगों की भीड़ देख रहा हूं, उससे साफ है कि पहले चरण का रिकॉर्ड भी टूटेगा और वोटिंग 90 फीसदी से भी ज्यादा होगी। अगर ऐसा हुआ तो समझ लेना परिवर्तन होने वाला है, लेकिन जीत की घोषणा होने से पहले मैं कुछ नही कहूंगा क्योंकि यह नियमों के खिलाफ है। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती भले ही इस बार चुनावी मैदान में नहीं हैं, लेकिन पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि फिलहाल वे चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। मिथुन लगातार मंचों से टीएमसी पर जमकर निशाना साध रहते रहे। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर बंगाल में दोबारा टीएमसी आ जाती है तो उनका और बाकी हिंदुओं का बंगाल में रहना मुश्किल हो जाएगा और उन्हें अपने रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक अपने हालिया बयान में अभिनेता ने टीएमसी पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया था। बंगाल में मछली-मांस बंद करने के आरोपों को खारिज करते हुए मिथुन ने कहा कि देश के कई राज्य हैं, जहां मछली-मांस खाया जा रहा है। देश में विशेष और धार्मिक पशु गाय के मांस को बेचने और खाने पर पाबंदी है। किसी भी राज्य में मछली-मांस खाने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। टीएमसी के पास कोई और तरीका नहीं बचा है और वे अब भ्रामक प्रचार फैलाकर जनता को परेशान करना चाहती है।

तुर्की के दुश्मन देश ग्रीस में अपनी जबरदस्त पैठ बनाने में जुटा भारत

ग्रीस का एलेक्जेंड्रो पोलीपोट बंदरगाह भारतीय कंपनी को सौंपने की तैयारी

नई दिल्ली(एजेंसी)। नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत के दोस्त देश ग्रीस से एक बड़ी खबर सामने आई है। ग्रीस का वहां बंदरगाह जो पूरे यूरोप की धड़कन कहा जाता है। अब भारत की मुट्ठी में आने वाला है। खबर है कि ग्रीस का एलेक्जेंड्रो पोलीपोट अब एक भारतीय कंपनी के अधिकार क्षेत्र में है। भारत की दिग्गज कंपनी बंदरगाह पोलीपोट को खरीदने या इसमें बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने ग्रीस सरकार के साथ बातचीत कर रही है। यह डील सिर्फ बिजनेस के लिहाज से नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत को सात समंदर पार स्थापित करने के लिहाज से बड़ी उपलब्धि है। पोलीपोर्ट की अहमियत को समझने के लिए इसकी लोकेशन बहुत जरुरी है। यह बंदरगाह बुल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन जैसे देशों के बिल्कुल करीब है। जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है। तब से यह पोर्ट पूरे यूरोप के लिए लाइफ लाइन बन गया है। नाटो देशों के टैंक हो, हथियार हो या फिर अनाज और गैस की सप्लाई हो सब कुछ इसी रास्ते से यूरोप के अंदर जा रहा है। और इसकारण कल तक जिस बंदरगाह को ग्रीस सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताकर बेचने से रोक दिया था। आज वहीं इसकी चाबी भारत को सौंपने की तैयारी की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सबसे बड़ा एंगल चीन और

तुर्की का है। ग्रीस का सबसे प्रमुख बंदरगाह पीरियस वर्तमान में पूरी तरह चीन की कंपनी कॉस्को के नियंत्रण में है। ग्रीस और बाकी यूरोपीय देश इस बात को लेकर परेशान है कि अगर उनके सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर चीन का कब्जा रहा, तब भविष्य में उनकी स्वायता खतरे में आ सकती है। भारत की एंट्री ने ग्रीस को एक भरोसेमंद विकल्प दिया है। भारत की छवि एक इसतरह के देश की है जो बिजनेस करता है लेकिन दूसरे देशों की जमीन या संप्रभुता पर कब्जा नहीं करता। वहीं तुर्की की ग्रीस से दुश्मनी किसी से नहीं छुपी और जब तुर्की पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। भारत का ग्रीस में होना तुर्की को बहुत खटकने वाला। भारत के लिए यह बंदरगाह एक गोल्डन गेट की तरह है क्योंकि भारत काफी समय से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईएमसी पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद भारत के सामान को अरब देशों के रास्ते सीधे यूरोप पहुंचाना है।

एलेक्जेंड्रो पोलीपोट कॉरिडोर का वहां आखिरी पड़ाव हो सकता है जहां से भारतीय माल पूरे यूरोप के बाजारों में फैल जाएगा। इससे ना सिर्फ भारत का निर्यात बढ़ेगा बल्कि स्वेज नहर जैसे रास्तों पर भारत की निर्भरता भी कम हो जाएगी। वहीं पोर्ट पर भारत का होना मतलब यूरोप की सप्लाई चेन और सुरक्षा के समीकरणों में भारत की परमानेंट सीट पक्की होगी। ग्रीस कैन रिपोर्ट्स पर जहां रूस और अमेरिका जैसे देशों की नजरें टिकी हैं। वहीं एलेक्जेंड्रो पोली में भारत की दावेदारी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। यह डील भारत की उस विदेश नीति का हिस्सा है जिसमें हम सिर्फ अपने पड़ोस तक सीमित नहीं है बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं।

'डिजिटल अरेस्ट' पर सख्ती: ठगों के मोबाइल नंबर और बैंक खाते ब्लॉक करने की तैयारी

सिम सत्यापन से लेकर बैंकिंग निगरानी तक कड़े उपाय

नई दिल्ली (एजेंसी)। देशभर में तेजी से बढ़ रहे 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे साइबर ठगी के मामलों पर अब केंद्र की मोदी सरकार ने सख्त रुख दिखाया है। इस बढ़ते खतरे को देखकर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश कर ठगों के मोबाइल नंबर और बैंक खातों को ब्लॉक करने सहित कई कड़े कदमों का खाका तैयार किया है। रिपोर्ट के अनुसार, समस्या से निपटने के लिए दूरसंचार, डिजिटल प्लेटफॉर्म और बैंकिंग तंत्र के बीच समन्वित कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने दूरसंचार विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक जैसे प्रमुख संस्थानों को एक साथ काम करने के निर्देश देने की मांग की है, ताकि सुरक्षा उपायों को समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सके।

दूरसंचार क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव सिम कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में देखने को मिलेगा। मोदी सरकार 'बायोमैट्रिक पहचान सत्यापन प्रणाली' को अनिवार्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिससे फर्जी सिम कार्ड के इस्तेमाल पर रोक लग सके। इसके अलावा, सिम सक्रियण से जुड़े पॉइंट ऑफ सेल (पीएसओ) एजेंटों के लिए भी कड़े सत्यापन और जवाबदेही नियम लागू किए जाएंगे।केंद्र की सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में प्रस्ताव है कि साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाले संदिग्ध मोबाइल नंबरों और सिम कार्डों को तुरंत ब्लॉक करे। साथ ही, दूरसंचार कंपनियों को जांच एजेंसियों के साथ रियल-टाइम डेटा साझा करने के निर्देश दिए जाएंगे, ताकि अपराधियों तक तेजी से पहुंचा जा सके।

डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका को लेकर भी मोदी सरकार सतर्क है। रिपोर्ट में व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म के लिए 'सिम-बाइंडिंग' और उन्नत सुरक्षा तंत्र लागू करने की बात की गई है। इसके तहत संदिग्ध कॉल्स और लंबी धोखाधड़ी वार्ताओं की पहचान कर उन्हें रोका जा सकेगा। साथ ही, स्कैम में इस्तेमाल होने वाले डिवाइस की पहचान कर उन्हें ब्लॉक करने की व्यवस्था भी तैयार की जा रही है। वित्तीय क्षेत्र में, मोदी सरकार ने बैंक खातों पर तत्काल कार्रवाई के लिए नई व्यवस्था सुझाई है। भारतीय रिज़र्व बैंक की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत संदिग्ध खातों पर अस्थायी डेबिट रोक लगाने का प्रावधान लागू किया जाएगा। इससे धोखाधड़ी के मामलों में पीड़ितों के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम में अपराधी खुद को पुलिस या जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और जुर्माना या सुरक्षा फीस के नाम पर पैसे ठगते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में इस तरह के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है और इसका शिकार आम नागरिकों से लेकर अधिकारी और बुजुर्ग तक हो रहे हैं।

हाईकोर्ट ने आसाराम बापू की अंतरिम जमानत अवधि 25 मई तक बढ़ाई

-नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम

जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने आसाराम बापू की अंतरिम जमानत अवधि 25 मई तक बढ़ा दी है। आसाराम की जमानत अवधि 6 मई को खत्म हो रही थी। आसाराम ने जमानत अवधि बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था। उस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की बेंच ने बुधवार को आसाराम की जमानत अवधि को 25 मई तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आसाराम की ओर से पैरवी करते हुए उनके वकील यशपाल राजपुरोहित ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट उनकी अपील पर सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रखा है। उन्होंने कहा कि आसाराम का इलाज

अभी जारी है। ऐसे में इलाज पूरा होने तक जमानत की अवधि बढ़ाई जाए। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को 29 अक्टूबर 2025 को जमानत दी थी। कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की डिवीजन बेंच ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया था।

रिपोर्ट के मुताबिक याचिका मेडिकल आधार पर लगाई गई थी। राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को तब पहली बार जमानत मिली थी। इससे पहले अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद उसने 30 अगस्त 2025 को सरेंडर किया था। बता दें नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अप्रैल 2018 से आजीवन कारावास की सजा आसाराम काट रहा है। करीब 12 साल की कैद के बाद पहली बार 7 जनवरी 2025 को उसे मेडिकल कारणों से अंतरिम जमानत दी गई थी।

राजस्थान हाईकोर्ट में 29 अक्टूबर 2025 को आसाराम की सजा स्थगन और मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की याचिका पर सुनवाई हुई थी। आसाराम की ओर से दिल्ली से आए सीनियर वकील ने पैरवी की थी। राजस्थान सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक चौधरी ने दलील रखीं। पीड़िता की ओर से एडवोकेट पीसी सोलंकी ने पैरवी की। सभी पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने 6 महीने की जमानत दी थी। यह जमानत 6 मई 2026 को खत्म हो रही थी।

क्रूड ऑयल की किल्लत से अब भारत में सड़क बनाना भी हुआ मुश्किल

-ईरान ने होर्मुज को कर रखा है बंद तो अमेरिका ने कर रखी है नाकाबंदी

नई दिल्ली (एजेंसी)। ईरान-अमेरिका की बीच दूसरे चरण की वार्ता ना होने से तेल बाजार एक बार फिर उछाल आया। एक उम्मीद जगी थी कि शायद जल्द ही होर्मुज खुल जाए। हालांकि अब इसका कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में ब्रेंट ऑइल की कीमतें 2.5 फीसदी की वृद्धि के साथ 107.97 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान की तरफ से ट्रंप के सामने एक नया प्रस्ताव रखा गया है। इसमें कहा गया है कि होर्मुज खोलने को लेकर पहले बात होनी चाहिए और परमाणु मुद्दे पर बात बाद में भी हो सकती है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वैसे तो अमेरका और ईरान के बीच युद्धविराम चल रहा है लेकिन होर्मुज का रास्ता अब भी बंद है। एक तरफ अमेरिका ने नाकेबंदी कर रखी है। इसी वजह से ईरान भी होर्मुज को खोलने को तैयार नहीं है। इसके चलते उर्वरक, प्राकृतिक गैस, फ्यलू और कच्चे तेल की सप्लाई ठप हो गई है। जानकारों का कहना है कि अगर स्थितियां ऐसी ही बनी रहीं तो आने वाले समय में कच्चे तेल की कीमतों में और इजाफा होगा। वहीं पेट्रोल और डीजल की किल्लत बढ़ सकती है।

लाइव लॉन्ग वेल्थ के संस्थापक और शोध विश्लेषक ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव, विशेषकर होर्मुज के आसपास की स्थिति और अमेरिका-ईरान वार्ता में गतिरोध से वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ी है। इससे कच्चे तेल की कीमतों पर सीधा असर पड़ रहा है और ब्रेंट क्रूड 107 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए ऊंची तेल कीमतें सबसे अहम आर्थिक कारक हैं, क्योंकि इससे महंगाई, रुपए और कंपनियों के मुनाफे पर दबाव पड़ता है।

अमेरिका-ईरान के बीच जारी तनाव और कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने से यूपी में सड़कों के निर्माण के लिए डामर (बिटुमिन) का संकट गहरा गया है। इसका असर हमीरपुर जिले में लोक निर्माण विभाग की सड़क परियोजनाओं पर साफ दिखाई दे रहा है। कई सड़कें अधर में लटक गई हैं, जबकि कुछ स्थानों पर गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि सड़क निर्माण में उपयोग होने वाला डामर क्रूड ऑयल से तैयार होता है और भारत में इसके लिए ईरान समेत अन्य देशों से कच्चे तेल का आयात किया जाता है। अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव से इसकी आपूर्ति प्रभावित हुई है।

उन्होंने बताया कि जब ठेकेदारों ने टेंडर डाले थे, उस समय डामर की कीमत करीब 42 हजार रुपए प्रति मीट्रिक टन थी, लेकिन अब जीएसटी समेत यह बढ़कर करीब एक लाख रुपए प्रति मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। डामर की कीमतों में इस भारी वृद्धि से ठेकेदारों में हड़कंप मचा है।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक,मुद्रक एवं संपादक ओमप्रकाश जांगिड़ के लिए स्काईटेक प्रिंटर से मुद्रित एवं प्लॉट नंबर 244 श्याम नगर विस्तार सांगानेर से प्रकाशित फोन नंबर 9784657775 सहायक संपादक, धर्म सिंह गुर्जर, सहयोगी संपादक एवं संरक्षक मुकेश कुमार टेलर पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के लिए जिम्मेदार ईमेल samudayaknews@gamil.com संपादकीय कार्यालय 105, डीपी कार्प ओके प्लस बिल्डिंग, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर